सुख की सरकार
हिमाचल सरकार

गिरिराज

हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

साप्ताहिक

ISSN 2454-9738

डाक पंजीकरण संख्या
एच.पी./42/एस.एम.एल. 2024-2026
साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

इस अंक में

विकासात्मक लेख - 5-7, स्वतंत्रता दिवस पर विशेष लेख-8-9, पहाड़ी पृष्ठ-10

वर्ष 46 अंक 46 शिमला, 14-20 अगस्त, 2024 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 5.00 रुपये वार्षिक 250 रुपये आजीवन 2500 रुपये

कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर व्यय होंगे तीन सौ करोड़

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में घोषणा की कि प्रदेश में कैंसर से ग्रसित मरीजों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की जाएंगी और उनका इलाज भी पूरी तरह से निःशुल्क पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पेल्लिएटिव केयर प्रोग्राम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह चिंता का विषय है तथा इसी के दृष्टिगत कैंसर के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान करेगी। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। इन दवाइयों में कैंसर

कैंसर रोगियों को निःशुल्क मिलेंगी 42 दवाएं

उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला ट्रासटूजूम्ब टीका भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये होती है। ब्रैस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए वर्ष में ऐसे 18 टीकों की आवश्यकता होती है। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर प्रदेश सरकार लगभग सात लाख रुपये व्यय करेगी। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में लोगों के घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 300 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए। इसके तहत 75 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कैंसर केयर हमीरपुर की आधारभूत संरचना, 75 करोड़ रुपये चमियाणा शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा तथा 150 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में विश्व स्तरीय कैंसर उपचार उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान दे रही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका महत्त्वपूर्ण हिस्सा (शेष पृष्ठ 11 पर)

आपदा प्रभावित परिवारों को आगामी तीन माह तक दी जाएगी आवास के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत दिनों शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त, 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड ब्वॉय के 47, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।

आईजीएमसी, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाणा में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है।

आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाणा अस्पताल में सुपर- स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डरली- सह-ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का एक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) एंड मिनरल्ज (प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत, राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली (शेष पृष्ठ 11 पर)

मंत्रिमंडलीय निर्णय

- सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 999 पद
- हिम उन्नति योजना के तहत स्थापित होंगे 2600 कृषि समूह
- हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज एंड मिनरल्ज नियम-2015 में संशोधन
- शहरी विकास निदेशालय में बनेगा पर्यावरण प्रभाग

चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होंगी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए साधन और संसाधनों को व्यापक स्तर पर सृजित और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को भविष्य की जरूरतों और तकनीक के आधार पर सुदृढ़ करने तथा संसाधन सृजन पर बल दिया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषयों की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कमियों को चिन्हित कर उनका उचित समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणात्मक चिकित्सा देखभाल के लिए छह मरीजों के अनुपात पर एक स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों से परामर्श के लिए प्रतीक्षा अवधि कम की जाएगी और परामर्श अवधि बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। मरीजों के पंजीकरण (शेष पृष्ठ 11 पर)

छह मरीजों के अनुपात पर एक नर्स होगी तैनात

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर बल देगी सरकार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 10 मेगावाट और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। प्रदेश आगामी छह माह में लगभग 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अधिकारियों (शेष पृष्ठ 11 पर)

स्वतंत्रता दिवस : महान लोकतंत्र का गौरवपूर्ण उत्सव

डॉ. राजेश शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

15 अगस्त का दिन भारत के इतिहास तथा हर देशवासी के जीवन में महत्त्वपूर्ण एवं विशेष है। इसी पावन दिन सैंकड़ों वर्षों की दासता के उपरान्त हमारा देश, विदेशी शासन से मुक्त हुआ। इसके बाद ही यह दिन भारत के इतिहास में एक विशेष दिवस के रूप में अंकित हो गया। प्रत्येक भारतीय इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाता है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं लाखों अन्य वीर सपूतों ने आजादी पाने के लिए एक लम्बा संघर्ष किया। अनेकों ने अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी स्वाधीनता संघर्ष में झोंक दी। अनेक महान सपूतों ने ब्रितानीय हुकूमत की यातनाएं सहीं तथा अनेक सुपूतों ने कालकोठड़ी के अंधकार में अपना जीवन समर्पित किया ताकि भारत आजादी का सूरज देख सकें तथा प्रत्येक भारतीय के जीवन में स्वतंत्रता का प्रकाश हो सके। स्वतंत्रता की इस लड़ाई का नेतृत्व महान नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। खून-पसीना बहाकर तथा अपने सर्वस्व का निःस्वार्थ त्याग कर अनेक सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया तथा करोड़ों भारतीयों को तत्कालीन ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। यह पावन दिवस हम सभी को उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने तथा उनके महान बलिदान को याद करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त यह दिवस हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा राष्ट्र के उत्थान व विकास के लिए निरंतर काम करने का संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है। इस पावन अवसर पर हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का गौरवपूर्ण उत्सव भी मनाते हैं। हमारा यह महान राष्ट्र विश्व के लिए लोकतंत्र की जननी है। अनेक महान क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप हम स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और हमें अवसर मिला अपने स्वयं के भविष्य निर्धारण का तथा स्वयं के लिए विकास व प्रगति के पथ को चुनने का। यह देश का सौभाग्य रहा कि स्वाधीनता के उपरान्त देश की बागडोर पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व, विचारक व राजनीतिज्ञ को मिली, जिन्होंने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक ठोस नींव रखी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी स्वाधीनता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रजामण्डल आंदोलन, धामी गोली कांड, पझौता आंदोलन, सुकेत सत्याग्रह आदि कुछ ऐसी घटनाएं थीं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश की ओर आकर्षित किया। यही नहीं, प्रदेश के अनेक लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिन्द (शेष पृष्ठ 11 पर)

प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में नवाचार से संवरेगा छात्रों का भविष्य

✍ अदिति

राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नवोन्मेषी पहल की जा रही है ताकि विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकें और हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरे। शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 1029 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 498 कला संकाय, 335 नॉन मेडिकल और 196 मेडिकल संकाय के शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र और प्रवक्ताओं के 486 पद, स्कूल कैडर प्रिंसिपल के 157 पद और विशेष देखभाल वाले बच्चों के स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे गए हैं। प्रदेश सरकार शैक्षणिक अधोसंरचना को भी सुदृढ़ कर रही है जिसके तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और आधुनिक पुस्तकालय शुरू किए गए हैं। 850 शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा किया गया है और वर्चुअल क्लासरूम और छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह कदम सरकार की दूरगामी सोच के परिचायक हैं। खेल से स्वास्थ्य योजना के तहत 110 शैक्षणिक संस्थानों को स्पोर्ट्स मैट और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 40 हजार स्कूल डेस्क और 29 सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए महज एक फीसदी ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। चार लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब तक इस योजना के तहत 5.25 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं ताकि धनराशि की कमी विद्यार्थियों के सपने साकार करने में बाधा न बने। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 में 81,618 विद्यार्थियों को 5419.29 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। श्री निवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के तहत 10वीं, 12वीं और महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता हासिल करें और भविष्य की नवीन तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के तहत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। सरकार उच्च विद्यालय छोटा शिमला, सलोह (ऊना) और उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली आठ करोड़ रुपये के बजट के साथ पूरी तरह से स्मार्ट विद्यालयों और महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जा चुके हैं। सीखने का अनुभव बेहतर बनाने के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक पुस्कालय स्थापित किए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने पोस्ट ग्रजुएट कैलेंडर की शुरुआत करते हुए स्नातकोत्तर शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक गतिविधि योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 के अकादमिक सत्र से वार्षिक अध्ययन दिवसों को 180 से 210 करना है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सुधार के लिए एकीकृत परीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष में दो जॉब फेयर आयोजित करना अनिवार्य किया है, इनमें स्थानीय विशेषज्ञों और उद्यमियों को शामिल करते हुए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।

कम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों का विलय और वर्ष में अकादमिक सत्र के दौरान तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला विद्यार्थियों के हितों के मद्देनजर लिया गया है। इससे शिक्षा में गुणवत्ता मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस रणनीतिक कदम से संसाधनों का अनुकूलन और शिक्षा का समावेश सुनिश्चित होगा। सरकार ने शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की पहल की है। इस पहल के तहत पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर के भ्रमण पर गए और वहां शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन किया। इसके अलावा अन्य 200 शिक्षक केरल और अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानक कायम करना, सुविधाओं से शिक्षकों के ज्ञान को तराश कर भविष्य के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवाने का मंच प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर किए जा रहे यह सुधार सरकार के समर्पण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। सरकार के इन महत्वाकांक्षी प्रयासों से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा जोकि आत्मनिर्भर बनने की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 1029 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 498 कला संकाय, 335 नॉन मेडिकल और 196 मेडिकल संकाय के शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र और प्रवक्ता के 486 पद, स्कूल कैडर प्रिंसिपल के 157 पद और विशेष देखभाल वाले बच्चों के स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे गए हैं।

दुग्ध क्षेत्र के विकासोन्मुखी कार्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश

✍ अनिल गोमा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों कहा कि दुग्ध उत्पादन रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला सशक्तीकरण की सम्भावनाओं का रास्ता प्रशस्त करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सहकारी समितियां भी सराहनीय कार्य कर रही हैं। प्रौद्योगिकी के युग में नवीन तकनीक और नवोन्मेषी पहल अपनाना नितांत अनिवार्य है। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण और इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध संयंत्रों का भी चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है। हिम-गंगा योजना के तहत जिला कांगड़ा स्थित ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इस संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाउडर बनाया जाएगा, जिसमें मांग से अधिक दूध को लम्बे समय तक संरक्षित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आईसक्रीम, लेवर्ड मिल्क, पनीर और अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इस संयंत्र में अल्ट्रा हीट तकनीक से पैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को किसानों व एकत्रीकरण केंद्रों से दूध प्रसंस्करण संयंत्रों तक दूध ले जाने के लिए 200 रेफ्रिजरेटिड मिल्क वैन उपलब्ध करवाने का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और दुग्ध संयंत्र ऊना की क्षमता 20-20 हजार लीटर करने की योजना भी बनाई है। दुग्ध विपणन प्रक्रिया और इसके परिवहन का युक्तिकरण भी किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन समितियों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाई है। इसके लिए समितियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ (मिल्कफेड) के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मिल्कफेड के ट्रेडमार्क 'हिम' का केंद्र सरकार से पंजीकरण करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड द्वारा राज्य में 102 ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण दूध एकत्र करने के लिए 320 लीटर क्षमता के 55 मिल्क कूलर छोटी समितियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1148 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनके 47,905 सदस्य हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 19,388 है। राज्य में 11 दुग्ध संयंत्र और 116 बल्क मिल्क कूलर भी स्थापित हैं। प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में 360 डिग्री विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों की आर्थिकी को संबल प्रदान किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और पशुपालकों को न केवल दूध उत्पाद का लागत आधारित मूल्य सुनिश्चित हो बल्कि उन्हें गुणवत्ता बोनस भी प्राप्त हो। सरकार इसी ध्येय के साथ निरंतर कार्य कर रही है। पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर क्रमशः 45 और 55 रुपये किया गया है। भारतवर्ष में यह पहल करने वाला हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि दुग्ध क्षेत्र के विकासोन्मुखी कार्यक्रमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश कर हिमाचल को इस क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाया जाए।

कांगड़ा के ढगवार में 250 करोड़ से विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 200 रेफ्रिजरेटिड मिल्क वैन उपलब्ध करवाने का बजट में प्रावधान

राज्यपाल ने आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया बल

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित विशेष सत्र के दौरान गत दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आम लोगों से जुड़ने, संचार के साधनों का बेहतर उपयोग करने तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका पर अपनी प्रस्तुति दी।

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य में जिला स्तर पर विभिन्न अवसरों के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया है। उन्होंने मौके पर ही लोगों की समस्याओं के निवारण के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों पर जनता द्वारा आवश्यक मांगें भी प्राप्त हुई, जिन पर रेडक्रॉस और विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती रही है। उन्होंने कहा कि राजभवन की इस पहल के बाद विभिन्न जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजनों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, निःक्षय मित्र आदि योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। आपदा राहत के दौरान भी लोगों से काफी सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के दौरान सेना के अधिकारियों ने भी स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।

हिम ईरा हाट में परोसे जाएंगे हिमाचली व्यंजन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने गत दिनों कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत नालदेहरा में 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित किए गए हिम ईरा हाट के भवन का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिम ईरा हाट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार स्थानीय व्यंजनों को परोसना तथा जैविक खाद से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफार्म देना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इस हिम ईरा हाट में पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिला के उत्पाद बेचने के लिए रखे जाएंगे जो कि पूर्ण रूप से जैविक होंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री ने छोटा शिमला में भी हिम ईरा हाट एवं प्रीमियम स्टोर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला ने शिमला शहर में निर्मित किए गए छः बुक कैफे में से तीन बुक कैफे न्यू शिमला, चौड़ा मैदान तथा छोटा शिमला को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालन के लिए उपलबध करवाए हैं जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेचने तथा स्थानीय व्यंजनों को परोसने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इस पहल के लिए उन्होंने नगर निगम महापौर सुरेन्द्र चौहान, समस्त नगर निगम पार्षदों तथा अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला मण्डल तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफी समय से उनके द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए उचित जगह की मांग की जा रही थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने महिलाओं की मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए नगर निगम से बातचीत की और अब यह हिम ईरा हाट एवं प्रिमियम स्टोर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इन भवनों में स्थानीय युवाओं को पढ़ने की सुविधा भी होगी साथ ही वे स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार विभिन्न व्यंजनों तथा उत्पादों का आनंद भी उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लिफ्ट के नजदीक नगर निगम पार्किंग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दो करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े स्तर का विक्रय केन्द्र बनाया जा रहा है जो अगले छः महिने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस विक्रय केन्द्र में प्रदेश के हर जिला को स्थान दिया जाएगा ताकि उस जिला की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने-अपने स्थानीय उत्पादों को बेचकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। साथ ही हमारे पारम्परिक व्यंजन, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी संभव हो सकेगा।

शिमला के नालदेहरा में 40 लाख से निर्मित हिम ईरा हाट का शुभारंभ, महिलाओं की आर्थिकी को मिलेगा संबल

जन सेवाएं 'हिम-एक्सेस' पर होंगी उपलब्ध

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की लाभार्थियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिम-एक्सेस नाम से एक असेंनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह बात डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों एवं सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागीय एप्लीकेशन्स की सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा और इन एप्लीकेशन्स द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। हिम-एक्सेस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन्स में एकरूपता और त्रुटिरहित डाटा सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस पोर्टल को अक्तूबर, 2024 तक तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को इस पोर्टल से जुड़ी सेवाओं के लाभ अक्तूबर से मिलने शुरू हो जाएंगे।

विभागीय एप्लीकेशन्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल हो रहा विकसित

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 19 लाख परिवारों एवं उनके सदस्यों को हिम पोर्टल के माध्यम से 'हिम परिवार' एवं 'हिम सदस्य कार्ड' शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार एक एप्लीकेशन विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा मौजूदा समय में प्रदान की जा रही 261 सेवाओं को भी हिम-एक्सेस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सुरक्षित रखने के पुख्ता प्रबन्ध किए जाएं।

उन्होंने एक माह के भीतर ई-केवाइसी पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि मिल्कफेड और प्राकृतिक खेती के लिए भी विभाग शीघ्र ही वेबसाइट तैयार करें।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को डिजिटल माध्यम से सभी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी मानव त्रुटियों को न्यून करते हुए बेहतर डाटा प्रबन्धन सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। आधुनिक तकनीक के विभागीय कार्यप्रणाली में एकीकरण से प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी प्रणाली स्थापित होती है।

दृढ़ इच्छाशक्ति व मेहनत से कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित मेधावी छात्रों के साथ

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के 'मेधावी छात्र सम्मान समारोह-2024' में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के 222 टॉपर विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें दसवीं कक्षा के 92 तथा बारहवीं के 90 टॉपर शामिल हैं, जबकि शिमला शहर के 40 टॉपर विद्यार्थी भी सम्मानित किये गये। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से सभी मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को बधाई दी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार ने नीतियों में बदलाव लाकर 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सभी विद्यार्थियों को 25-25 हजार की घोषणा, 222 टॉपर विद्यार्थी सम्मानित

उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है जिसके लिए शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फैसला किया गया है। गरीब और गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की सोच के साथ राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सात प्रतिशत से 83 प्रतिशत पहुंच गई है। प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय लगभग 300 शिक्षण संस्थान थे, जो आज बढ़कर 16 हजार से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा विभाग में 7000 खाली पदों को भरा जा रहा है तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए शिक्षा क्लस्टर सिस्टम भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अध्यापकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण भी कराया है।

राज्यपाल ने किया पौधरोपण

हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रास सोसायटी और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पौधरोपण अभियान में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्यतिथि भाग लिया। उन्होंने शिमला के अन्नाडेल के निकट ग्लेन में देवदार का पौधा रोपित किया। अभियान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्नाडेल स्कूल के जूनियर रेडक्रास स्वयं सेवकों ने 250 पौधे रोपित किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक होने की आवश्यकता है। उन्होंने पौधरोपण अभियानों में सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ-साथ हमें उनका संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदेश में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं चिंता का विषय है, जिसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण योजना के तहत पौधारोपण के लिए वन विभाग को 150 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इस राशि का उद्देश्य राज्य में हरित आवरण को विस्तार प्रदान कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन विभाग ने राज्य में नौ हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी और राज्य रेडक्रास के स्वयं सेवक भी उपस्थित थे।

पुलिस को 25 पेट्रोलिंग मोटर साइकिल प्रदान

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों चौड़ा मैदान, शिमला से यातायात के सुचारू संचालन और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शिमला और नूरपुर पुलिस जिला के लिए हाई विजिबिलिटी क्षमता की 25 पेट्रोलिंग मोटर साइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रथम चरण के दौरान लगभग 3.72 करोड़ रुपये की लागत से शिमला के लिए 19 और नूरपुर पुलिस जिला के लिए छह पेट्रोलिंग मोटर साइकिलें प्रदान की गई हैं। शिमला जिला में पुलिस के लिए 30 हैंडहेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी वॉर्न कैमरे, 18 एल्को सेंसर, 30 स्पीड कैमरे, 80 स्पीड ब्रेकर, 225 रिफ्लेक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बैटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिकेड और 30 सर्चलाइट उपलब्ध करवाई गई हैं। कांगड़ा व मंडी जिलों में भी सड़क सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यातायात प्रवर्तन, निगरानी, बचाव और सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया में पुलिस की क्षमता में सुधार के लिए 27 करोड़ रुपये से विभिन्न उपकरणों की खरीद की जा रही है, जिनमें राजमार्ग पेट्रोलिंग के लिए शिमला, कांगड़ा और मंडी के लिए 42 चार पहिया वाहन और कांगड़ा और मंडी के लिए 27 दो पहिया वाहन, क्षेत्र प्रवर्तन के लिए 14 इंटरसेप्टर वाहन, बचाव कार्यों के लिए रेकर वाहन और हैंडहेल्ड स्पीड गन, बचाव कार्यों के लिए हाइड्रोलिक उपकरण, आपातकालीन बैग, वाहन संचालित गति संकेत उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों की खरीद मार्च, 2025 से पहले पूरी कर ली जाएगी और इन्हें शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों के पुलिस स्टेशनों में वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए विभिन्न गश्त निगरानी बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण खरीदने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

उपकरण खरीद पर लगभग 90 करोड़ का होगा निवेश

शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 61.57 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। यह प्रणाली शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में विभिन्न सड़कों पर 214 चिन्हित स्थानों पर एआई सुविधा से लैस 532 कैमरों से जुड़ी होगी। उन्होंने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना, पुलिस के लिए गश्त, सड़क सुरक्षा प्रवर्तन में सुधार के लिए उपकरणों की खरीद सहित पुलिस और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रदेश सरकार ने दस माह में निपटाए 1.87 लाख से अधिक राजस्व मामले

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों कहा कि प्रदेश में अक्तूबर, 2023 से जुलाई, 2024 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,63,268 इंतकाल, 9,417 तकसीम, 12,453 निशानदेही और 2,427 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 जुलाई, 2024 को 10,746 इंतकाल, 408 तकसीम और 541 निशानदेही के मामले निपटाने के साथ-साथ 131 राजस्व त्रुटियों को सुधारा गया। इसके अतिरिक्त जुलाई, 2024 में 16,514 इंतकाल, 554 तकसीम और 2,142 निशानदेही तथा 464 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया और जुलाई माह में कुल 31,500 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को घर-द्वार पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है।

जुलाई में ही 31500 राजस्व मामलों का किया निपटारा

उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से वर्षों से लंबित पड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही आमजन को राहत मिल रही है और लंबित राजस्व मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अक्तूबर, 2023 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवस में इन लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जाता है ताकि लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पारदर्शी और त्वरित प्रशासन प्रदान करने को अधिमान दे रही है।

सरकार द्वारा लिए गए जन हितैषी निर्णयों से लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जन-जन की सरकार है और आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर उनका समाधान किया जा रहा है।

विद्युत शेडयूलिंग से होगी 200 करोड़ की आय

हिमाचल प्रदेश को विद्युत की शेडयूलिंग और बेहतर लेखा प्रबंधन से प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की आय होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी) ने विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेडयूलिंग और लेखा प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए एक नई प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों कहा की नई प्रक्रिया से प्रदेश को सेंटर सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से अपनी अधिकारिक मुफ्त बिजली के हिस्से को सीधे उत्पादन केंद्र से बस बार आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विद्युत की सटीक शेडयूलिंग और लेखांकन हो पाएगा। सीधे उत्पादन केंद्र से अपने हिस्से की बिजली बेचने से ट्रांसमिशन शुल्क की बचत होगी और अन्य कई तरह के नुकसान भी न्यूनतम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन केंद्रों के बस बार से मुफ्त विद्युत की शेडयूलिंग और लेखा प्रबंधन से विद्युत का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। हिमाचल में अनेक परियोजनाएं दशकों से कार्यशील हैं। इस प्रक्रिया के लागू होने से राजस्व बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आय सृजन के साधनों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे नाथपा झाकड़ी और रामपुर विद्युत परियोजनाओं में गाद की समस्या के दौरान प्रदेश को विद्युत कट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान राज्य अपने शेडयूल को संशोधित नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य एजेंसियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है, जिससे राज्य में विद्युत प्रबंधन व आय सृजन संसाधनों में सुधार सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र द्वारा अप्रैल, 2024 से जुलाई, 2024 तक विद्युत विक्रय से पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले सरकार को 300 करोड़ रुपये की अधिक आय हुई है।

बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ जारी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री गत दिनों उद्योग विभाग की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्माण से संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में स्थल विकास, सड़कें, डिस्चार्ज ट्रीटमैंट संयंत्र, भाप उत्पादन, डक्टिंग सहित विभिन्न संरचनाओं का विकास कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि इन सभी संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही कार्य योजना पर दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए।

हितधारकों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की अन्य विभिन्न परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की तथा निविदा, वित्तीय संसाधन, भूमि हस्तांतरण आदि मामलों को लेकर तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ आम लोगों को समयबद्ध सुनिश्चित किया जा सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विभाग की परियोजनाओं में हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकसित हिमाचल की अवधारणा को पूरा करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं।

कुल्लू के आपदा प्रभावितों के लिए भेजी राहत सामग्री

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गत दिनों राजभवन शिमला से कुल्लू जिले के लिए राहत सामग्री के दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट और कंबल भेजे गए। राज्यपाल ने लोगों से बरसात के दौरान हर समय सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत पर्यटकों से भी नदी-नालों के किनारे न जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को निरंतर राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आग्रह पर तुरंत राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य के लोगों से इस कठिन समय में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया।

गिरिराज
हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। आंतरिक स्वतंत्रता लोभ व व्यय आदि विकारों से मुक्त रहना और बाह्य स्वतंत्रता इच्छानुसार आचरण करना है -महर्षि अरविंद

आजादी का पर्व

पंद्रह अगस्त का दिन भारत के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हमने 1947 में इसी दिन ब्रिटिश उपनिवेशी ताकतों से भारत की धरती को मुक्त करवाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस देश के असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई तथा हजारों को कारावास व काले पानी की यातनाऐं झेलनी पडी। इन लोगों के कड़े संघर्ष व बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब हम मानसिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर आजाद है। हमारा अपना संविधान और मौलिक अधिकार है। आजादी पाने के बाद यहां के मेहनतकश लोगों ने कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कला, साहित्य, खेल इत्यादि के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इससे हमारा लोकतन्त्र न केवल मजबूत हुआ है बल्कि वैश्विक मंचों पर भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज हमें उन महान स्वतंत्रता सैनानियों और शहीदों के आदर्शों का अनुसरण करने की आवश्यकता है जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी ताकि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया जा सके। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसक तरीके से लड़ा गया। यह अपनी तरह का एक अनोखा जन आंदोलन था जिसमें हिमाचल के लोगों ने भी बढ़चढ़ कर भाग लिया। फिर चाहे वह प्रजामंडल आंदोलन हो या धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह हो या पझौता आंदोलन इन सभी घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत तो पन्द्रह अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन हिमाचल की जनता अभी भी पहाड़ी रियासतों के अधीन थी। उन्हें आजादी के ठीक आठ महीने के उपरान्त 15 अप्रैल, 1948 को यहां की रजवाड़ा शाही से आजाद होने का मौका मिला। तब से शुरू हुई इस विकास यात्रा के दौरान इस पहाड़ी प्रदेश ने कई उतार-चढ़ाव देखे। अनेक भौगोलिक विषमताओं व चुनौतियों से घिरे इस प्रदेश ने दिखा दिया कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाता है। स्वतंत्रता के उपरान्त जब यह पहाड़ी प्रदेश अस्तित्व में आया तो उसे आर्थिक तंगी और आधारभूत सुविधाओं की बहुत सी कमियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में कई मंजिलें तय कर स्वयं को देश के मानचित्र पर अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। तब से लेकर अब तक इस पहाड़ी प्रदेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विकास के हर क्षेत्र में कई मंजिलों को पार किया। इस उपलब्धि का श्रेय जहां यहां के ईमानदार और मेहनतकश लोगों को जाता है वहीं समय-समय पर प्रदेश के मिले सशक्त नेतृत्व को भी जाता है जिन्होंने इस सुन्दर पहाड़ी क्षेत्र को एक विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही जन हित में कई मर्मस्पर्शी व कड़े निर्णय लेकर यह साबित कर दिया कि वे सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। सरकार का एक मात्र ध्येय जन सेवा करना व प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखकर अपनी पहली ही मंत्रिमण्डल की बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया और महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की अपनी प्रतिज्ञा को अमलीजामा पहनाया। जरूरतमंद असहाय व निराश्रित बच्चों व महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक सौ एक करोड़ रुपये की धन राशि से मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित कर यह साबित कर दिया कि वे जो कहते हैं उसे अपनी करणी में भी लाते हैं। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जिससे बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास हो रहा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ देखने में जितने सुन्दर लगते हैं उतने ही बरसात के मौसम में जानलेवा व घातक सिद्ध हो रहे हैं। बरसात के मौसम में भारी वर्षा होने के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान व माल का नुकसान उठाना पड़ता है। विगत दो वर्षों से मानसून के सीजन में अप्रत्याशित वर्षा और बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी आपदा का सामना करना पड़ रहा है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा विपदा की इस घड़ी में प्राथमिकता के आधार पर राहत एवं बचाव कार्य कर बाढ़ प्रभावितों को हर सम्भव सहयोग दिया जा रहा है।

स्वाधीनता संग्राम में हिमाचल प्रदेश

✍ रीना नेगी

हमारी स्वाधीनता असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के अनथक निःस्वार्थ संघर्ष का परिणाम है। समस्त भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था तो हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा। अंग्रेजों के शासन के समय गर्मियों की राजधानी शिमला में जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता यहां पर आते थे तो हिमाचल वासियों में भी समूचे राष्ट्र के साथ आजादी हासिल करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई।

यहां के निवासियों के संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है। जिसकी शुरुआत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व हो गई थी। 1846 ई. के ऐंग्लो-सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। मार्च 1846 ई. को लाहौर सन्धि के अंतर्गत कांगड़ा की पहाड़ी रियासतें अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। कुल्लू, लाहौल-स्पीति भी अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गए। इस प्रकार हिमाचल में सिख शासन का अन्त हुआ और हिमाचल का निचला क्षेत्र ब्रिटिश कम्पनी सरकार के प्रभुत्व में आ गया।

इस युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों ने मण्डी, सुकेत और चम्बा के राजाओं को शिमला क्षेत्र के शासकों की भांति राज्य लौटा दिए और शासन में आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान की। परन्तु लाहौल-स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, जसवां, गुलेर, नूरपुर, दतारपुर, हमीरपुर, कोट्ला आदि के शासकों के राज्य छीन लिए और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिए। शासकों की छोटी-छोटी जागीरें आवंटित की, जिससे शासकों में रोष व्याप्त हुआ। वर्ष 1848 में कांगड़ा के शासकों ने गुप्त मंत्रणा की। नूरपुर के वजीर रामसिंह पठानिया ने जम्मू क्षेत्र से सेना का प्रबन्ध कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रामसिंह ने शाहपुर किले पर कब्जा कर लिया व नूरपुर के राजा वीरसिंह के नाबालिक पुत्र जसवन्त सिंह को राजा घोषित किया। अंग्रेजों ने जालन्धर के कमिश्नर हैनरी लॉरेंस के नेतृत्व में सेना भेजी। अन्त में अंग्रेजों की विजय हुई और राम सिंह पंजाब होकर गुजरात चला गया। जसवां, कांगड़ा और दतारपुर के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ। अन्त में राजा प्रमोद चन्द, जगत चन्द, उमेद सिंह और उसके पुत्र जयसिंह को पकड़कर देश निकाला दे कर अलमोड़ा जेल में नज़रबन्द कर दिया।

1849 में राम सिंह पठानिया ने दो सिख रेजिमेंटों और पहाड़ी फौज के साथ शाहपुर के उत्तरपूर्व की ओर 'डल्ले की धार' नामक पहाड़ी से अंग्रेजों को ललकारा और उन के बीच घमासान युद्ध हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर राबर्ट पील का भतीजा लैफ्टीनेंट जॉन पील इस युद्ध में मारा गया। अन्त में राम सिंह पठानिया की पराजय हुई। उसे बंदी बनाकर सिंगापुर जेल में डाल दिया गया। 1857 से पहले हुए संघर्ष के पहले इस योद्धा की मृत्यु सिंगापुर जेल में हुई।

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर यहां पर कई क्रांतियां हुईं, जिनमें हमारे प्रदेश के लोग जो उस समय छोटी-बड़ी रियासतों में बंटे पहाड़ी लोग आजादी की इस लड़ाई में शामिल होने लगे थे। 1857 में जतोग, कसौली, धर्मशाला, रामपुर तथा कुल्लू इत्यादि क्षेत्रों में सशस्त्र क्रांतियां हुई।

1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला पहाड़ों में भी भड़की। कसौली छावनी में भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व सूबेदार भीम सिंह द्वारा किया गया। सुबाथू के राम प्रसाद बैरागी को फांसी दी गई। रामपुर बुशहर के राजा शमशेर द्वारा ब्रिटिश सरकार को नजराना देने से इंकार किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कुल्लू के राजा प्रताप सिंह और उसके साले वीर सिंह को फांसी हो गई। जतोग में सैनिक विद्रोह हुआ।

1859 ई. में रामपुर बुशहर में लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों व बेगार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया गया। 1862 में सुकेत में राजा और उसके बजीर के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया। 1876 में पुनः लोग एकत्रित हुए और आन्दोलन किया। इस विद्रोह का कारण 'खार अन्न' लगान था।

1877 में नालागढ़ के बजीर के विरुद्ध विद्रोह हुआ। 1883 में बिलासपुर में रियासत के अधिकारियों के दमन तथा अन्याय के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस सत्याग्रह का उद्देश्य आत्मपीड़न और आत्मदाह द्वारा राजा और उसके प्रशासक के अत्याचारों और तानाशाही के प्रति विरोध प्रकट करना था। 1884 ई. में राजा ने शहीद हुए सत्याग्रहियों की विधवाओं में पेंशन लगा दी और रियासत छोड़ कर गये ब्राह्मण परिवारों को वापिस बुला लिया।

1885 की तारीख भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। इस काल में अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इस दौर में कुछ विदेशी भी भारतीय प्रजा के समाज कल्याण और जन जागृति के कार्यों में सक्रिय थे। इनमें श्रीमती ऐनी बेसेन्ट, कर्नल ऑलकाए, मैडम बलावतस्की, विलियम बैडरबर्न, मिस्टर सिन्नेट्ट, एलन आक्टेवियन ह्यूम, मैडम ह्यूम प्रमुख थे। ह्यूम ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों से मतभेद के कारण भारतीय राजकीय सेवा से समय पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये। 1882 में वे शिमला आए और अपने भवन 'रोथनी कैसल' में रहने लगे। 1883 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें देश की स्वाधीनता प्राप्त करने का आह्वान किया गया था। वे भारतीयों को अपने हितों के बारे पत्रों, सम्मेलनों के माध्यम से जागरूक करते रहे। इस प्रकार ह्यूम ने भारत के सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से विचार विमर्श के उपरान्त एक राष्ट्रव्यापी संगठन स्थापित करने की घोषणा की। 28 दिसम्बर, 1885 को बम्बई में देशभर के 72 सदस्यों ने बंगाल के वोमेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई।

ह्यूम ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों से मतभेद के कारण भारतीय राजकीय सेवा से समय पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये। 1882 में वे शिमला आए और अपने भवन 'रोथनी कैसल' में रहने लगे। 1883 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें देश की स्वाधीनता प्राप्त करने का आह्वान किया गया था। वे भारतीयों को अपने हितों के बारे पत्रों, सम्मेलनों के माध्यम से जागरूक करते रहे।

1895 ई. में चम्बा रियासत में सार्वजनिक किसान आन्दोलन हुआ। राजा शाम सिंह और वज़ीर गोविन्द राम के प्रशासन में किसानों पर भूमि लगान का भारी बोझ था। भटियात वजीरी के किसानों ने आर्थिक शोषण के विरुद्ध पूरी वजीरी में असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। इसी तरह 1897 में बाघल रियासत में भी भूमि लगान के विरोध में प्रजा ने आन्दोलन किया। 1898 में बेजा तथा ठियोग की ठकुराइयों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रजा में राजनीतिक जागृति और गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती थी। कांग्रेस, आर्य समाज, ब्रह्म-समाज, प्रार्थना सभा, सनातन-धर्म और अन्य सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यकलापों का प्रभाव पहाड़ी जनता पर बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने के बावजूद स्थानीय आन्दोलन होते रहे। 1905 में बाघल रियासत में प्रजा ने खुला विद्रोह किया। 1906 में बुशहर रियासत में जबरदस्त किसान आन्दोलन हुआ।

1909 में मण्डी रियासत में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राजा भवानी सेन का वजीर जीवानन्द पाधा एक भ्रष्ट, अत्याचारी और दुष्ट प्रशासक था। उसने किसानों को डरा-धमका कर सारे अनाज का व्यापार अपने नियंत्रण में कर लिया। शोभाराम के नेतृत्व में 20 हजार लोगों ने विरोध किया। जालन्धर, कुल्लू और कांगड़ा से बुलाए गये सेना दलों द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। 1914-15 में गदर पार्टी से सम्बद्ध 'मण्डी षड्यन्त्र' में भाई हिरदाराम को आजीवन कारावास और रानी खैरागढ़ी को देश- निष्कासन। गदर पार्टी में सम्बद्ध हरदेव (स्वामी कृष्णानंद) में देश-विदेश में भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया गया।

1920 में कुनिहार के राजा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जन प्रतिनिधियों को यातनाएं तथा कारावास भेजा गया। 1920-23 में शिमला में कांग्रेस का गठन कर सक्रिय आन्दोलन किया गया। वहीं 1927 में सुजानपुर कांग्रेस आन्दोलन में ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांशी राम, गोपाल सिंह, चतर सिंह को कारावास की सजा दी गई। वर्ष 1930 में बिलासपुर में बंदोबस्त के विरुद्ध हुए अभियान में 19 व्यक्तियों को कारावास दिया गया।

वर्ष 1930 में 27 फरवरी को महात्मा गांधी ने देश में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' आरम्भ करने की घोषणा की। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार प्रमुख रहा। शिमला, कांगड़ा, सुजानपुर, कांगड़ा जनपद कुल्लू में आन्दोलन फैला। 12 अक्तूबर, 1930 को पंजाब तथा पहाड़ी रियासती प्रजा का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में हुआ। जनवरी, 1931 तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन के संघर्ष में हिमाचल के 1500 आन्दोलनकारियों को जेल की सजा हुई। 1923 में स्वामी पूर्णानंद के नेतृत्व में मण्डी में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। 1934 में सिरमौर प्रजामण्डल की स्थापना की गई। प्रजामण्डल आन्दोलन के लिए स्वामी जी को नौ मास का कारावास हुआ। 1936 में हिमालयन स्टेट्स लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई।

1939 में चम्बा, मण्डी, बिलासपुर, बुशहर, जुब्बल, सिरमौर तथा अन्य पहाड़ी रियासतों में प्रजामण्डलों की सक्रियता से गठन किया गया। 13 जुलाई, 1909 को भागमल सोहटा की अध्यक्षता में शिमला हिल स्टेट्स प्रजा मण्डलों की बैठक हुई। 1939 में धामी गोली कांड की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेताओं का ध्यान इस पहाड़ी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हिमाचल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन आते रहे। इस समय आम जनता को दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। एक तरफ रजवाड़ा शाही दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध क्योंकि अंग्रेज शासकों द्वारा इस पहाड़ी क्षेत्र के सीधे-सादे लोगों को पिछड़ा और असभ्य समझकर हीन तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार के दोषपूर्ण प्रशासनिक व सामाजिक नीतियों के कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी।

1941 में सिरमौर के नरेश से राजनीतिक मतभेदों के कारण डॉ. यशवन्त सिंह परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दिया। सिरमौर रियासत से डॉ. परमार का निष्कासन हुआ। 1942-43 में पझौता के किसानों द्वारा आन्दोलन। 10 व 11 जून, 1943 को गांव कोटी में गोलीकाण्ड। आन्दोलन में भाग लेने के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों को कारावास में डाल दिया गया।

1943 से 1946 के मध्य डॉ. परमार ने दिल्ली में रहकर पहाड़ी लोगों को संगठित किया और पहाड़ों में प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए रणनीति तैयार की। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र में प्रजामण्डल की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी। हिमालयन हिल स्टेट्स रिजनल कौंसिल की स्थापना की गई। पदमदेव, शिवानन्द रमौल, पूर्णानन्द, डॉ. यशवन्त सिंह परमार, दौलत राम सांख्यान द्वारा अलग पर्वतीय राज्य की स्थापना का संकल्प लिया गया। प्रजामण्डल की प्रेरणा से मण्डी, कुनिहार, जुब्बल, कोटी, ठियोग, बुशहर आदि में प्रतिनिधि सरकारों का गठन हुआ व प्रशासन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई।

15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ। हालांकि पहाड़ को भौगोलिक परिस्थितियां विकट थी। साधनों की कमी थी। लेकिन देश को विदेशी दास्तां से आजाद करवाने का जज्बा पहाड़ से भी ऊंचा था।

ग्रामीण आर्थिकी

कृषि-बागबानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

✍ योगराज शर्मा

प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों ने सदियों से ही हमारी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और कड़ी मेहतनत करने वाले लोगों को पोषित किया है। लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए भी ग्रामीण आर्थिकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिन्हें दूर किया जाना अति आवश्यक है। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाना समय की मांग है। वर्तमान प्रदेश सरकार भी इन्हीं महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य कर आगे बढ़ रही है ताकि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा सके।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के करीब 90 फीसदी लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं जिनमें से 70 प्रतिशत सीधे तौर पर कृषि कार्यों से जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगोंको गांवों में ही शहरों जैसी सुविधाएं मिल सके और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वर्तमान सरकार ने कृषि, बागबानी एवं पशुपालन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकास का रुख गांवों की ओर मोड़ा है ताकि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा सके। राज्य सरकार के सार्थक प्रयासों से गांवों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो रहा है। सरकार द्वारा कृषि-बागबानी सहित सड़कों व पुलों के निर्माण के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र को विशेष तरजीह दी जा रही है। प्राकृतिक खेती में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के तीसरे चरण में एक नई योजना 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना' शुरू की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में, प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को 'ज़हर मुक्त खेती' के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के लिए सरकार राज्य में ड्रोन तकनीक को अपनाने पर भी जोर दे रही है।

हिमाचल प्रदेश जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में किसानों व बागबानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से ड्रोन तकनीक काफी मददगार साबित होगी। इसकी मदद से मौसम का सही पूर्वानुमान, सिंचाई की बेहतर सुविधा, कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव व फसल के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त करने में बागबानी एक महत्त्वपूर्ण घटक है। बागबानी न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रही है अपितु इससे जुड़ा व्यवसाय काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा है। इससे नौ लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।

यह सर्वविदित है कि हिमाचल की पहचान एक सेब राज्य के रूप में है। यहां लगभग आठ जिलों के लोग सेब बागबानी से आर्थिक रूप से समृद्ध, स्वावलंबी एवं सम्पन्न हुए हैं। बाजार में हिमाचल का सेब किसी अन्य देश के सेब से कम न आंका जाए तथा यह आयातित सेबों की प्रतिस्पर्धा कर सके, इसके दृष्टिगत सरकार ने कई बागबान हितैषी निर्णय लिए हैं। बागबानों की लम्बे अर्से से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सेब को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही पेटियों में भरा तथा मण्डियों में इसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए, जिसमें पैकिंग मैटीरियल का भी भार शामिल है। इससे प्रदेश के बागबान व्यापक रूप से लाभान्वित होंगे तथा उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा।

किसानों-बागबानों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा फल मण्डियों का स्तरोन्नयन व आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार फल केन्द्र विकसित कर रही है। इसके दृष्टिगत सरकार ने सोलन जिले के परवाणु व सोलन में 28.38 करोड़ की लागत से सेब व फल मण्डियों का आधुनिकीकरण कर उन्हें स्तरोन्नत किया है। इन फल मण्डियों के स्तरोन्नत होने से बागबानों को सेब व अन्य फलों के क्रय-विक्रय में सुविधा होगी। इसके साथ ही शिमला जिले के पराला में 100.42 करोड़ से निर्मित अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का भी मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया है। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जा रहा है। किसानों-बागबानों को राहत पहुंचाने के लिए हाल ही में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम के फलों की खरीद का मूल्य 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने और गलगल की खरीद 10 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से खरीदने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश की गर्म जलवायु वाले निचले क्षेत्रों में बागबानी की आपार संभावनाओं को देखते हुए उपोष्ण कटिबंधीय बागबानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) अहम भूमिका निभा रही है। परियोजना के तहत नए बगीचे लगाने के लिए बागबानों को उपयुक्त पौध सामग्री से लेकर सामूहिक विपणन तक सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं। बीज से बाजार तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को क्लस्टर एप्रोच में वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कृषि के साथ-साथ फसलोपरांत मूल्यवर्धक करते हुए बाजार से जोड़ा जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये है। इसमें से एशियन विकास बैंक 1030 करोड़ व हिमाचल सरकार 262 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना में किया जा रहा है। इस से राज्य के 15 हजार किसान-बागबान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

ढांचागत सुविधाएं

आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए विकासात्मक अधोसंरचना का सृजन

✍ लुभित सिंह

विकास की राह भविष्य को ध्यान में रखकर प्रशस्त होती है। इसके साथ ही विकास के लिए अधोसंरचना सृजन बेहद आवश्यक है। विकासात्मक अधोसंरचना के सृजन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रही है। इसमें प्रदेश हित में लिए गए मुश्किल निर्णय भी शामिल है। विचार-विमर्श को निर्णय का रूप देना राज्य सरकार की विशेषता है, जिसके कारण यह लोकप्रिय भी बनी है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में एक अलग मुकाम मिला है। हिमाचल का नाम सुनते ही पर्यटकों के ख्यालों में मनोहर दृश्य, सुंदर पहाड़ियां, बर्फ से ढकी चोटियां, स्वच्छ वातावरण व हरियाली अनायास ही आ जाती है। इन सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है। अनछुए स्थलों को भी पर्यटकों के लिए तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पौंग बांध में साहसिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। कांगड़ा के बीड़-बीलिंग में पैरा-ग्लाइडिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता और शिमला के जुन्गा में पहली बार फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित कर साहसिक पर्यटन में हिमाचल को विश्व के मानचित्र पर लाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष दो से नौ नवम्बर तक कांगड़ा के बीड़-बिलिंग में विश्व पैराग्लाइडिंग कप आयोजित किया जाएगा। यह हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा, जिसमें प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पांच हेलीपोर्ट के निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है। शिमला का संजौली हेलीपोर्ट जल्द ही कार्यशील किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर के गोबिंदसागर और ऊना के अंदरौली में जलक्रीड़ा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लाहौल-स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी व किन्नौर के रकछम, नाको, चांगो और खाब में नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा कुफरी के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन सैलानियों के अनुभव को चिरस्मरणीय बना रहा है।

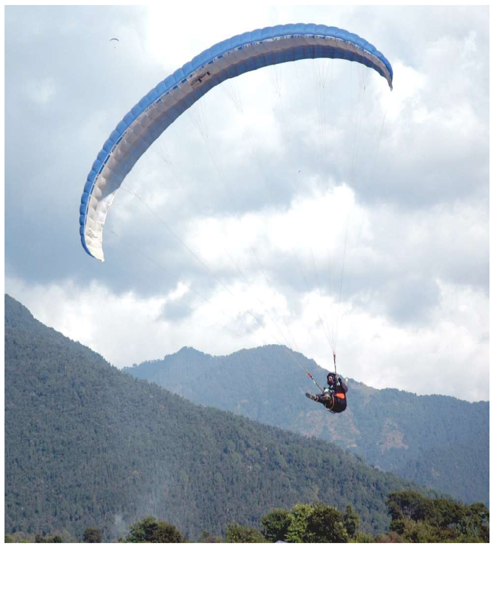

प्रदेश में यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए परिवहन अधोसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। सड़कों की क्रॉस ड्रेनेज को प्राथमिकता दी गई है। नए पुल बनाने पर बल दिया जा रहा है। गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों की नियमित टारिंग भी की जा रही है। बरसात के कारण बंद सड़कों को खोला जा रहा है और क्षतिग्रस्त सड़कों को दोबारा बनाकर यातायात को सुचारू बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य परिवहन साधनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनमें रोप-वे प्रमुख है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए रोपवे को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध, बगलामुखी, शिमला, बिजली महादेव के अलावा धर्मशाला, किलाड़, नारकंडा-हाटूपीक, जाबली-कसौली, शिरगुल महादेव, पुंडरिक ऋषि मंदिर रोपवे भी प्रस्तावित है। इन रोपवे के बनने से हिमाचल की पहचान पर्यटन क्षेत्र में और सुदृढ़ होगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से वर्ष 2024 की पहली छमाही में राज्य में एक करोड़ से अधिक पर्यटक भ्रमण पर आए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादन से जहां पशुपालक जुड़े हैं वहीं विभिन्न हितधारक भी इससे अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। दुग्ध प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुग्ध संयंत्रों का भी चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है। हिम गंगा योजना के तहत जिला कांगड़ा के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता को बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इसमें दूध पाउडर, दही, खोया, घी, पनीर, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और अन्य दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाएंगे। पशुपालकों से दूध एकत्रित करने और दूध प्रसंस्करण संयंत्रों तक दूध ले जाने के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफ्रिजरेटिड मिल्क वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल दिया जा रहा है। फार्मा एक्सपो मुंबई में 2110 करोड़ रुपये के निवेश के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। हरित उद्योग पर चार हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति भी लाएगी। स्टार्ट-अप नीति के तहत नवाचार के लिए महिलाओं को स्टार्ट-अप आरम्भ करने के लिए एक वर्ष के लिए अधिकतम चार लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। प्रदेश में हिमाचल प्रदेश माइनस एण्ड मिनरल्स पॉलिसी लाई जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना है। वर्तमान प्रदेश सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसमें विकासात्मक अधोसंरचना के सृजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

शिक्षा

शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार

* आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी राजकीय पाठशालाओं में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का विकल्प
* प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाने का लक्ष्य
* 'पढ़ो हिमाचल' अभियान के तहत 500 शिक्षण संस्थानों में बनाए जाएंगे रीडिंग रूम
* लाहड़ू, नगरोटा बगवां, अमलेहड़, भोरंज और संगनाई में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण

बेहतर शिक्षण व्यवस्था की बात की जाए तो हिमाचल का नाम भारत के अग्रणी राज्यों में आता है। हमारे राज्य को देश में साक्षरता के लिहाज से दूसरे स्थान पर होने का गौरव हासिल है। शिक्षा अधोसंरचना व शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने लम्बे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने व प्रदेश के विभिन्न भागों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस वित्त वर्ष में सरकार शिक्षा के लिए नौ हजार 560 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर शिक्षण व्यवस्था के सुधार पर बल दे रही है।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व युक्तिकरण के लिए भी सुधारवादी कदम उठाएं हैं, जिसके तहत मंत्रिमंडलीय बैठक में दो किलोमीटर की परिधि में आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और तीन कि.मी. के दायरे में आने वाले माध्यमिक विद्यालयों में पांच व इससे कम विद्यार्थी नामांकन वाले संस्थानों का विलय करने का निर्णय लिया है। शिक्षण व्यवस्था का युक्तिकरण कर उसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से उठाए गए इस कदम के अलावा प्रदेश सरकार ने शून्य नामांकन वाले 89 प्राथमिक और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे इन स्कूलों को संचालित करने पर होने वाले व्यय को शिक्षा अधोसंरचना उन्नयन के उपयोग में लाया जा सके।

प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को मात्र किताबी ज्ञान न देकर उनको सक्षम बनाने के लिए रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। जिसके लिए सरकार राजकीय संस्थानों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी से अवगत करवाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी ही पहल है जिससे विद्यार्थियों को सीखने के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं और वे इंटरैक्टिव शिक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षणिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री की पहल पर अनेक पग उठाएं जा रहें हैं, जिसके तहत प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आरम्भ किया गया है।

आरम्भिक शिक्षा, शैक्षणिक व्यवस्था का आधार है, जिसे सुदृढ़ करने के लिए राज्य के लगभग छः हजार प्री-प्राइमरी विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है तथा शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में राजकीय संस्थानों को बेहतर बनाने की दृष्टि से आगामी शैक्षणिक सत्र में

✍ विवेक शर्मा

प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। संस्थानों के आधुनिकीकरण पर सरकार का विशेष बल है।

विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान कर उन्हें भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के उपयोग पर सरकार बल दे रही है। शैक्षणिक संसाधनों के समुचित दोहन के लिए उनके साझा उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध ढंग से इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस वित्त वर्ष में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें 500 प्राईमरी स्कूल 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल। पढ़ने की संस्कृति के लिए भी सरकार प्रयासरत है। इसके लिए एक नई योजना पर कार्य शुरू किया गया है। 'पढ़ो हिमाचल' नाम से इस योजना के तहत विद्यालयों के साथ जनसमुदाय को भी जोड़ा जाएगा तथा विशेषकर युवा पाठकों के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

सेहत

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

प्रदेशवासियों को आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार अनेक दूरगामी निर्णयों को मूर्त रूप दे रही है। इस वित्त वर्ष के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए तीन हजार चार सौ पंद्रह करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से रोबोटिक सर्जरी सुविधा आरम्भ की जा रही है ताकि रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ ऐमरजेंसी मेडिसन बनाने का निर्णय लिया गया है।

देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश में कैंसर से ग्रस्त मरीजों को मुफ्त दवाइयां प्रदान करने और उनका इलाज पूरी तरह से निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। राज्य में कैंसर पर रणनीति आधारित कार्य करने के लिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैल्लिएटिव केयर प्रोग्राम का गठन किया गया है। यह सुविधा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाएगी। सरकार अटल सुपर स्पेशिएलिटी संस्थान चमियाणा में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी आरंभ की जाएगी। राज्य में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री आरंभ की जाएगी। इसके तहत कैंसर के मामलों व संख्या का अध्ययन किया जाएगा।

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तीन हजार 415 करोड़ का बजट
- अटल सुपर स्पेशिएलिटी संस्थान चमियाणा में 75 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी बोनमैरो ट्रांसप्लांट सुविधा
- सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त होंगी प्रदान

सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान की जाएगी। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। इन दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला ट्रासट्रूजुमैब टीका भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये होती है। ब्रैस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए वर्ष में ऐसे 18 टीकों की आवश्यकता होती है। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर प्रदेश सरकार लगभग सात लाख रुपये व्यय करेगी।

प्रदेश में कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 75 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कैंसर केयर हमीरपुर की आधारभूत संरचना, 75 करोड़ रुपये चमियाणा शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा तथा 150 करोड़ रुपये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में विश्व स्तरीय कैंसर उपचार उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार जनकल्याण को सर्वोच्च अधिमान दे रही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य ध्येय है। सरकार कैंसर डे-केयर सेंटर चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर रही है। प्रथम चरण में 13 अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके दूसरे चरण में 27 हाई लोड सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेंटर स्थापित होंगे और तीसरे चरण में 28 संस्थानों में डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में पैल्लिएटिव केयर यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। हमीरपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहां न्यूक्लियर मेडिसन का विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा।

बल्क ड्रग पार्क

राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपये लौटाने निर्णय लिया है। मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण लेगी। अब परियोजना में फेरबदल करते हुए 25 प्रतिशत भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए और 75 प्रतिशत अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

प्रदेश की महिलाएं हो रहीं लाभान्वित

प्रदेश सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। महिलाओं को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना 13 मार्च को जारी की गई थी। अब तक सरकार को लाखों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने अभी 23 करोड़ रुपए की पहली किश्त राशि जारी की है। ये राशि जिला कल्याण अधिकारियों के जरिए संबंधित जिलों में महिलाओं के खाते में डाली जा रही है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन की गारंटी दी थी, जिसके तहत अब प्रदेश में लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले जा चुके हैं।

योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल और हिमाचल की स्थाई निवासी होना पहली शर्त है। इसके अलावा महिला के परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मी नहीं होने चाहिए। योजना के तहत 1500 मासिक पेंशन के लिए पात्र महिलाएं आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकती हैं। तहसील कल्याण अधिकारी ही इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे।

आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटोकापी, आधार कार्ड की फोटोकापी, राशन कार्ड की फोटोकापी आदि लगानी होगी। इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी समेत पूरे हों। अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा।

सरकार सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का लाभ देगी। जिला कल्याणकारी के पास छंटनी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवेदन जमा करने के लिए प्रक्रिया निरंतर जारी है। छंटनी की प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाली महिलाओं को आवेदन जमा करने की तारीख से ही सुविधा का लाभ मिलेगा।

आवेदन करने वाली जिन पात्र महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए पेंशन नहीं मिली है, उन्हें अब आवेदन जमा करने की तारीख से ही 1500 रुपए की राशि दी जाएगी।

हरित हिमाचल

पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ ऊर्जा का दोहन

वर्ष 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प

हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिकीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही रियायतों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ता जा रहा और इससे यहां स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इनमें बड़े तथा छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योग शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यावरण मित्र उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल व निर्बाध विद्युत आपूर्ति देश के बड़े औद्योगिक घरानों की निवेश के लिए यह पसंदीदा जगह रही है और वे सदैव ही यहां निवेश करने के लिए आकर्षित होते रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश को यहां की स्वच्छ जलवायु, निर्मल पर्यावरण, जवाबदेह प्रशासन, निवेशक मित्र नीतियां तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक परिदृश्य निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए एक पंसदीदा गंतव्य बनाते हैं। सरकार द्वारा जहां सिंगल विंडो स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए व्यापार सुगमता और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को बेहतर माहौल और बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने की दूरदर्शी सोच ने पहली बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वयं निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए नई पहल की है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश

आगामी छः माह में होगा 50 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन

औद्योगिक निवेश नीति को व्यावहारिक एवं निवेशक मित्र बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों को सभी वांछित स्वीकृतियां तुरन्त प्रदान करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। यह निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो उद्योग पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आईटी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, विद्युत, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में निवेशकों को वन स्टॉप सुविधा मिलेगी। रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप ऊना जिले के हरोली में स्थापित हो रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये निवेश होंगे तथा 15 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है।

सरकार ने विद्युत के क्रय-विक्रय के समन्वय के लिए एक पी.एस.ई.बी. एल., एन.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है इससे 24000 युवाओं के कौशल विकास के लिए कौशल विकास निगम 10 कौशल परिषदों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला ऊना के गगरेट के जीतपुर बेहरी में लगभग 500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश करेगी।

✍ चन्द्रशेखर वर्मा

प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण हिमाचल का पूरे देश में अपना विशेष स्थान है। बर्फ व वर्षा से पोषित यहां की नदियां प्रदेश को लगभग 27 हजार मेगावॉट की भरपूर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रदान करती है। आर्थिक संसाधन सृजन की बात की जाए तो राज्य के लिए पर्यटन, कृषि-बागवानी के साथ ऊर्जा एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने की दृष्टि से जल विद्युत कहीं बेहतर एवं पर्यावरण मित्र स्रोत माना गया है। प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त भी ऊर्जा उत्पादन के कई पर्यावरण मित्र स्रोत उपलब्ध है। पर्यावरण हितैषी दोहन के दृष्टिगत ही सरकार ने हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना का संकल्प लिया है और इस संकल्प को वर्ष 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इससे प्रदेश के 3500 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

सरकार ने 100 किलोवॉट से एक मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत उपदान देने का फैसला किया है। इस योजना से आगामी 25 वर्षों तक क्रय करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को इन्हें (परियोजनाओं) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा व उन्हें आय भी प्राप्त हो सकेगी।

प्रदेश के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने बेहतर आय सृजन के लिए ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को एक संयुक्त मंच प्रदान करते हुए 'एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क' स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने समझौता ज्ञापनों की समय-सीमा को 40 वर्ष कर दिया है। हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में 'ग्रीन पंचायतें' बनाई जा रही है। इन पंचायतों में 500 किलोवॉट से लेकर एक मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

जनजातीय क्षेत्र पांगी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित 'बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए वर्ष 2023-24 में 500 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल में जल व सौर ऊर्जा स्रोतों के अलावा सरकार पवन ऊर्जा के दोहन पर भी बल दे रही है। इसके लिए लाहौल-स्पीति ज़िला के काज़ा को 84 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा दोहन के लिए चिन्हित किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से शानन परियोजना पंजाब सरकार की लीज अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल को सौंपने के गंभीर प्रयास जारी है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड व नाथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन जैसी कम्पनियां जो पहले ही अपनी लागत पूर्ण कर चुकी से राज्य को 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने की वकालत की है। केंद्र सरकार से राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग भी गई है। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने से न केवल कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा बल्कि जलवायु परिवर्तन को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

विद्युत चालित परिवहन की ओर अग्रसर हिमाचल

पर्यावरण संरक्षण से हमारे अपने हितों का रक्षण होता है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष कदम उठाए हैं ताकि सभी को स्वच्छ वायु मिल सके। सरकार ने स्वच्छ परिवहन से ग्रीन हिमाचल की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन शुरू किया गया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश को मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चरणबद्ध रूप से इस लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को इलेक्ट्रिक वाहनों की दृष्टि से छह ग्रीन कॉरिडोर विकसित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। जिनके संचालन से वायु, ध्वनि और अन्य तरह के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना है। ई-वाहनों के संचालन में कोई समस्या न आए इसके लिए राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से 23 ई-चार्जिंग स्टेशनों को राज्य के विभिन्न पैट्रोल पंपों पर स्थापित किया गया है, जबकि वर्ष 2024-25 में 97 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रभावी नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों पर सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति के तहत निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान भी दिया जा रहा है। सरकार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है जिसके दृष्टिगत 680 करोड़ की सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण को शुरू किया है। योजना के तहत ई-टैक्सी के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं तथा मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। ई-टैक्सी के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट भी शुरु कर दी गई है। यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने में मील पत्थर सिद्ध होगी। ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। प्रदेश में अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 3740 है। निजी क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों की संख्या 3240 है। प्रदेश में 500 व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन भी पंजीकृत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास भी इस समय 110 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है जबकि ई-टैक्सियों की संख्या 50 है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए छह कॉरिड़ोर स्थापित किए गए हैं।

हाल ही में सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और अतिरिक्त दो हजार टाइप-2 बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने ई-बसों की फंडिंग के लिए नाबार्ड के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है।

चंबा में बनेगा प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन

प्रदेश में शीघ्र ही ग्रीन हाइड्रोजन से बसों का संचालन होगा। प्रदेश सरकार चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित करने जा रही है। यह स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस महत्त्वाकांक्षी हरित पहल का निर्माण नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगस्त 2025 तक पूरा किया जाएगा। यह संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यहां पर बस सुविधा के लिए एक हाइड्रोजन डिस्पेंसर यूनिट भी स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना एनएचपीसी चमेरा-3 पॉवर स्टेशन के निकट स्थापित की जाएगी और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे 300 किलोवॉट ग्रिड के सौर ऊर्जा संयंत्र से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से दुर्गम क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। इस बाबत एनएचपीसी चंबा ने बस खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यातायात के सुचारू संचालन और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत शिमला और नूरपुर पुलिस जिला के हाई विजिबिलिटी क्षमता की 25 पेट्रोलिंग मोटर साइकिलें दी हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 61.5 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। यह प्रणाली शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में विभिन्न सड़कों पर 214 चिन्हित स्थानों पर ए.आई. सुविधा से लैस 532 कैमरों से जुड़ी होगी। ग्रीन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को विशेष बल दिया जा रहा है। हिमाचल के वन आच्छादित क्षेत्रों को विस्तार प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है।

स्वतंत्रता

भारत विभाजन एक भयानक विभीषिका

✍ गौरीशंकर वैश्य विनम्र

भारत को 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली थी। 14 अगस्त, 1947 की तिथि इतिहास की महत्त्वपूर्ण तारीख है। उस दिन संविधान सभा रात 12 बजे के बाद तक चली। पंडित नेहरू ने कहा, 'थोड़ी देर बाद यह सभा एक स्वतंत्र संप्रभु देश का प्रतिनिधित्व करेगी।' उसी रात भारत स्वतंत्र हुआ। इसी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, 'हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि गरीबी, भूख, बीमारी, शोषण एवं भेदभाव मुक्त सुंदर जीवन वाला समाज बनाने की अथक कोशिश करेंगे। इसी बैठक में डॉ. राधाकृष्णन ने भाषण में कहा था - 'एक चिर प्रतीक्षित रात्रि के अवसान पर ऐसी रात्रि जो भाग्य निर्णायक शुभ घटनाओं से परिपूर्ण अर्थात् स्वातंत्र्य सूर्य के दर्शन'।

तब से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक वर्ष तक स्वतंत्रता का 'अमृत महोत्सव' अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उस अभियान का आह्वान किया, जो इस संकल्प को प्रेरित करें कि 25 वर्ष बाद जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएं, तब हम इसे कहां देखना चाहेंगे? इस अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन में आहुति देने वाले महान देशभक्तों का स्मरण आवश्यक है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना भारत के लिए गर्व का विषय है, इसको धूमधाम से मनाना भी चाहिए, किंतु इससे पूर्व 14 अगस्त 1947 का वह दिवस भी कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का सबसे रक्तरंजित अध्याय है। यह दिवस भारत को दो टुकड़ों में विभाजन की दुःखद याद दिलाता है, जो देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं है। 14 अगस्त, 1947 की सभा की कार्यवाही के पृष्ठों में अंकित सपने और आश्वासन असमय कालकवलित हो गए। यह अंग्रेजों की साजिश थी कि देश को टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसके लिए कुछ भारतीय नेता भी उत्तरदायी थे। एक तरफ 200 वर्षों की दासता के बाद स्वतंत्रता मिलने वाली थी, दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। इसकी त्रासदी को शब्दों में बांधना अथवा बता पाना संभव नहीं है। घटना तो वही लोग कह पाए जो जीवित बचे थे, लाखों की चीखें भी कोई नहीं सुन पाया। भारत के विभाजन के ढांचे को माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। 14 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का काला दिवस ही कहा जाएगा। इसी दिन भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया था। इसी दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया था और उसे स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा मिला।

भारत का विभाजन रक्तपात का एक दस्तावेज बन गया, जिसे हमेशा उलटना-पलटना आवश्यक है। स्मृति दिवस का आयोजन संदेश देता है कि देश अपनी सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही ऐसी दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कटिबद्ध भी।

इसी विभाजन दिवस ने विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, भयंकर रक्तपात हुआ। यह विभीषिका द्वितीय विश्व युद्ध (1939) और बंगाल के सूखे (वर्ष 1943 -44) से भी अधिक भयावह थी। पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशों से भरी कई ट्रेनें भारत भेजी गई थीं, लगभग 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लोगों ने अपनी बेटियों और बहिनों को स्वयं मार दिया जिससे उनकी लाज बच सके। हिंदुओं की संपत्ति लूटी गई और लाखों को पाकिस्तान से बलात विस्थापित कर दिया गया। विभाजन के समय पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला, शेखपुरा, मोंटगोमरी, झेलम, झंग, मुल्तान आदि से जो लोग आए थे, उनमें से सबसे अधिक करनाल और अंबाला में बसे थे। हरियाणा में रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में लगे 50 शिविरों में लगभग साढ़े चार लाख लोगों को शरण दी गई। कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े शिविर में 2.70 लाख लोगों को जगह दी गई। विभाजन के समय कुल 85 छोटे - बड़े शरणार्थी शिविर देश में लगाए गए थे।

इस दिन मात्र देश ही नहीं बंटा था कौम, धरोहर, धरती, सड़क, रेल, नकदी, नदियां, डाक टिकट, सोने की ईंटें, किताबें तक बंटी थीं। भारत कई त्रासदियों से गुजरा है, लेकिन इस बंटवारे की पीड़ा आजतक बंट नहीं पाई है।

भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके एक दिन पहले भारत विभाजन की त्रासदीपूर्ण घटना को अनेक इतिहासकारों और लेखकों ने अपने - अपने तरीके से इतिहास के पन्नों में समेटने का प्रयास किया है। अंग्रेज लेखक 'कोलिंस' और फ्रेंच लेखक 'लेपियरे' ने 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में इस घटना को 'इतिहास का सबसे जटिल तलाक' कहा है।

अनेक साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया है, इनमें पाकिस्तान मेल (खुशवंत सिंह), पिंजर (अमृता प्रीतम), तमस (भीष्म साहनी), कितने पाकिस्तान (कमलेश्वर), झूठा सच (यशपाल), सिक्का बदल गया (कृष्णा सोबती), मलबे का मालिक (मोहन राकेश), शरणदाता (अज्ञेय) आदि कृतियां उल्लेखनीय हैं। भारत - विभाजन की टीस हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के फिल्मकारों ने सिनेमा के पर्दे पर कई फिल्मों में दर्शाई। इसमें तेरी याद, फेरे, लाहौर, ट्रेन टू पाकिस्तान, गदर एक प्रेम कथा प्रमुख हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही हमें यही बताया जा रहा है कि विभाजन के समय की विभीषिका को भूल जाओ। कहा ही नहीं जा रहा है, इतिहास भी इसी सोच के अनुसार लिखा और लिखवाया गया।

मुगलों और मुस्लिम शासकों की लगभग आठ सौ वर्ष की गुलामी ही नहीं, विभाजन के समय भी हिंदुओं ने अपनी जन्मजात अहिंसक प्रवृत्ति और अपनी सीमा से बाहर जाकर युद्ध न लड़ने की परंपरा होने के कारण उन्होंने आत्मरक्षा के लिए भी आक्रामक पर कभी आक्रमण नहीं किया और रक्षापरक युद्ध करने की उनकी आदत शिथिल हो गई। विभाजन के समय भी हिंदुओं ने अपनी इसी नीति का कुफल भोगा।

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन की त्रासदी में लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं की याद में, 14 अगस्त, 2021 को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' को मनाने की घोषणा की। यह पहली बार 2021 में मनाया गया। यह 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है।

भारत सरकार ने, भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी को भारत विभाजन के अंतर्गत लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए यह स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन एवं वैमनस्यता के विष को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तीकरण की भावना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की याद दिलाएगा। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही इससे सामाजिक ऐक्य, स्नेह-सौहार्द और मानवीय संवेदनाएं भी सुदृढ़ होंगी।

इस ऐतिहासिक तिथि ने कई रक्तपात देखे, भारत का विभाजन रक्तपात का एक दस्तावेज बन गया, जिसे हमेशा उलटना-पलटना आवश्यक है। इतिहास को न तो भुलाया जा सकता है और न छिपाया जा सकता है। जब-जब इस तरह के प्रयास होते हैं, परिणाम बुरे ही निकलते हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि इसके आधार पर किसी से बदला लिया जाए।

यह स्मृति दिवस मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है, इससे वह हिंसक और असहिष्णु विचारधारा भी कटघरे में खड़ी होती है, जो इन त्रासदियों का कारण बनता है। केवल आत्म अवमानित या मृतप्रायः समाज ही विभीषिकाओं को भुला सकता है। स्मृति दिवस का आयोजन संदेश देता है कि देश अपनी सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही ऐसी दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी कटिबद्ध है।

कविता

भारत हुआ आजाद

✍ लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

प्राण दिए कितने वीरों ने,
तब आजादी आई।
पावन पर्व निराला था वह,
हमने खुशियां पाई॥

अंग्रेजों के हम गुलाम थे,
कुछ भी न थे अधिकार।
हम सत्य नहीं कह सकते थे,
न कर सकते तकरार॥

कहने की कोशिश करते थे,
कोई कभी जब बात।
अंग्रेज पीटते पकड़ हमें,
जेल में बीते रात॥

गांधी, सुभाष, भगत सरीखे,
आगे बढ़ कर आए।
एकजुट किए वे जनता को,
लोगों को समझाए॥

अनगिनत हुए आंदोलन तब,
दिखलाया खूब जोश।
आजादी के लिए बैठकें,
उर में समाया रोष॥

लाल, बाल और पाल जैसे,
देश से जिनको प्यार।
आजाद, तिलक से हुए वीर,
गोरों पर खूब वार॥

जेलों में वर्षों बंद रहे,
उनसे कोड़े खाए।
दिन-रात लड़े अंग्रेजों से,
फांसी गले लगाए॥

शहीद हुए जब माँ के लाल,
भारत हुआ आजाद।
वंदन-अभिनंदन वीरों का,
करें सदा उन्हें याद॥

कविता

मेरी मातृभूमि की माटी

✍ शिव सन्याल

मेरी मातृभूमि की माटी मुझे जान से प्यारी है।
वीरों ने लहू से रंग डाली दिव्य आभा न्यारी है।

फ़ौलादी सीना ताने उत्तर में हिमालय है खड़ा।
कनक चांदी अद्भुत मुकुट इसके माथे है जड़ा।
बहती नदियां सुधा लिए सींच रही मां माटी को,
दुश्मन की नजर लगे नहीं प्रहरी बनके है अड़ा।
ऋतुओं ने मातृभूमि की रज-रज संवारी है।
मेरी मातृभूमि की माटी मुझे जान से प्यारी है॥

ऋषि, मुनियों की तपस्थली यह देवालय नाम है।
अवतार लिए ईश्वर ने यहां सब से पावन धाम है।
इतिहास भरा बलिदानों से वीर कई मर मिट गये,
उनकी शौर्य गाथा आजादी का दे रही पैगाम है।
हिंदु मुस्लिम सिख ईसाई की फुलवारी है।
मेरी मातृभूमि की माटी मुझे जान से प्यारी है॥

मातृभूमि की रक्षा को हम अपना जीवन दे देंगे।
दुश्मन का सिर कलम करें देश हित यौवन दे देंगे।
देश के लिए जीना मरना मातृभूमि के प्रहरी हम,
तिरंगा न झुकने देंगे हम अपना तन मन दे देंगे।
विश्वगुरु बने भारत यह प्रतिज्ञा मन में धारी है।
मेरी मातृभूमि की माटी मुझे जान से प्यारी है।

स्वतंत्रता संग्राम में 'भारत माता' की गूंज

भारत में अपने देश को मातृभूमि के रूप में आराधना करने की परम्परा सदियों पुरानी है। विभिन्न धर्मग्रंथों में मातृभूमि को महिमामंडित करने से संबंधित कई श्लोक एवं प्रसंग मिलते हैं। लेकिन भारत माता को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से रूपायित किया गया था। वर्ष 1873 में बंगाल के लेखक किरण चन्द्र बनर्जी ने 'भारत माता' शीर्षक से एक नाटक लिखा। सर्वप्रथम इस नाटक में 'भारत माता' का उल्लेख किया गया था। यह नाटक बंगाल में अकाल पर केंद्रित था। धीरे-धीरे लोग भारत माता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र देवी के रूप में स्वीकार करने लगे। अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों ने 'भारत माता की जय' के उद्घोष को उत्साहपूर्वक अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जुलूस, सम्मेलन आदि में 'भारत माता की जय' का नारा जोर-शोर से लगाया जाता था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में 'भारत माता की जय' नारे का उल्लेख किया है। आज भी देश के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, जुलूस आदि में 'भारत माता की जय' का नारा लगाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'भारत माता की जय' का नारा देश की गली-गली में गूंजता है।

चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था। सन् 1905 में बनाये उनके चित्र में भारत माता के परिधान का रंग भगवा था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को चार भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया था। भारत माता के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में सफेद वस्त्र, तीसरे हाथ में धान की बाली तथा चौथे हाथ में माला को दर्शाया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस चित्र के माध्यम से भारत माता की संतानों यानि आम भारतीय की मूलभूत आवश्यकताओं ज्ञान, वस्त्र, भोजन एवं धर्म-कर्म को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह चित्र क्रांतिकारियों में काफी लोकप्रिय हुआ। वे भारत माता के इस चित्र को अपने पास सम्मानपूर्वक रखते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की मूल पेंटिंग कोलकाता के रवीन्द्र भारती सोसायटी के संग्रहालय में सुरक्षित है। हालांकि आजकल प्रचलित चित्र में भारत माता शेर पर सवार और हाथ में तिरंगा झंडा लिए दिखती हैं।

चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा सन् 1905 में बनाये गये भारत माता के चित्र को चार भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया था। भारत माता के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में सफेद वस्त्र, तीसरे हाथ में धान की बाली तथा चौथे हाथ में माला को दर्शाया गया था। इस चित्र के माध्यम से आम भारतीय की मूलभूत आवश्यकताओं ज्ञान, वस्त्र, भोजन एवं धर्म-कर्म को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान यह चित्र क्रांतिकारियों में बहुत लोकप्रिय था।

भारत माता के प्रथम मंदिर की स्थापना वाराणसी में वर्ष 1936 में हुई थी। इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध समाजसेवी शिवप्रसाद गुप्त ने करवाया था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। इस मंदिर में भारत माता की कोई छवि अंकित नहीं है बल्कि संगमरमर की नक्काशी में अविभाजित भारत का मानचित्र है। भारत माता का एक अन्य मंदिर हरिद्वार में स्थित है। इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा 15 मई,1983 को हुई थी। यह 180 फीट ऊंचा और 8 मंजिला है। मंदिर के पहली मंजिल पर ही भारत माता की मूर्ति विराजमान है। इस विशाल मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि ने की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर के निकट भारत माता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में भारत माता की विशाल पाषाण मूर्ति स्थापित है।

कन्याकुमारी में स्थित भारत माता मंदिर भी काफी लोकप्रिय है। यहां भारत माता की 12 फीट ऊंची पीतल की मूर्ति के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त देश के अलग-अलग हिस्सों में भी भारत माता की मूर्ति स्थापित है। जिसमें पुडुचेरी के बॉटनिकल गार्डन में स्थापित भारत माता की मूर्ति प्रमुख है। यह मूर्ति प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि सुब्रह्मण्यम भारती द्वारा तैयार डिजाइन पर आधारित है।

✍ कल्याणमय आनंद

लेख

करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 'टाइगर हिल' पर कब्जा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने 'दिल मांगे मोर' का नारा देकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया।

वीरता, शौर्य और बलिदान की याद

कारगिल दिवस भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण दिन है। यह दिन भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और बलिदान की याद में समर्पित है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में कई भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कारगिल युद्ध भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच लड़ा गया था। हर साल इस दिन हर हिंदुस्तानी गर्व से अपने शहीदों की शहादत को नमन करता है और वीर सैनिकों का सम्मान करता है। यह युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है।

पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर जिन जगहों पर कब्जा कर लिया था, भारत के जांबाज सैनिकों ने उन दुर्गम स्थानों पर दोबारा तिरंगा फहराया था। 60 दिन से ज्यादा चलने वाली इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और

✍ रवींद्र कुमार शर्मा

पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। लगभग तीस हजार भारतीय सैनिक और करीब पांच हज़ार घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली सभी जगहों पर हमला किया और पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला था। कारगिल युद्ध के मुख्य क्षेत्र थे द्रास क्षेत्र, बटालिक क्षेत्र, तोलोलिंग क्षेत्र, टाइगर हिल, मश्कोह घाटी, प्वाइंट 4875 क्षेत्र। टाइगर हिल कारगिल युद्ध का बहुत ही महत्त्वपूर्ण व चर्चित स्थान था। कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा और कई अन्य वीर जवानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया भारतीय सेना के एक वीर अधिकारी थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के प्रारंभिक दिनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कारगिल क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान सेना के साथ मुठभेड़ में पकड़े गए थे। उन्हें व उनकी टीम को पाकिस्तानी सेना ने बहुत यातनाएं दी थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था तथा सारे देश में पाकिस्तान के प्रति नफरत ने उग्र रूप ले लिया था। उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा को 'शेरशाह' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्वाइंट 5140 और प्वाइंट 4875 पर कब्जा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने बटालिक सेक्टर में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को प्वाइंट 4875 पर वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। संजय कुमार हिमाचल प्रदेश की कोट्धार के गांव बकैन के रहने वाले हैं। मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने टोलोलिंग पहाड़ी को छुड़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने भी युद्ध में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कर्नल ललित राय ने भी अद्वितीय नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन किया। इनके अलावा, कई अन्य सैनिकों और अधिकारियों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की रक्षा की और वीरता के अनेक उदाहरण पेश किए।

कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को तब हुई जब एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल जिले के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली है जबकि यह क्षेत्र भारतीय सीमा में आते थे और इन पर कब्जा करके पाकिस्तान ने सर्दियों के दौरान भारतीय सैनिकों की अनुपस्थिति का लाभ उठाया था। तब भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 27 मई को कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से इस पूरे क्षेत्र को मुक्त करा लिया।

यह घुसपैठ एक रणनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को काटना और सियाचिन ग्लेशियर के समीप भारतीय सैनिकों की आपूर्ति लाइन को बाधित करना था। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन बद्र' का नाम दिया था।

कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। इन ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों में लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय जवानों ने अपनी ताकत, प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता से सभी चुनौतियों का सामना किया।

करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे।

कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 'टाइगर हिल' पर कब्जा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने 'दिल मांगे मोर' का नारा देकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इसी तरह कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने खालूबार में अद्वितीय वीरता दिखाई, ने अपने अंतिम शब्दों 'ना छोड़नू' से देशभक्ति का सन्देश दिया। इस विजय ने न केवल भारतीय सेना के शौर्य को साबित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। इस युद्ध ने भारतीय सेना की क्षमता, रणनीति और अद्वितीय साहस को प्रदर्शित किया और देशवासियों में राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना को और मजबूत किया।

दो कविताएं

मैं सैनिक हूं

माँ मुझको बंदूक दिला दो,
सीमा पर लड़ने जाऊंगा।
भारत मां की रक्षा खातिर,
मैं अपना फर्ज निभाऊंगा॥

छुपे हुए उन गद्दारों को,
मार-मार उन्हें भगाऊंगा।
आंख उठाए दुश्मन जो भी,
मैं सबको सबक सिखाऊंगा॥

आंधी आए या तूफान,
मैं कभी नहीं घबराऊंगा।
बम गोली की बौछारों से,
भारत का मान बढ़ाऊंगा॥

छोटे-छोटे इन कदमों से,
चोटी पर मैं चढ़ जाऊंगा।
अब मैं सैनिक बनकर ऊंचा,
सदा तिरंगा फहराऊंगा॥

✍ सुशीला साहू

पंद्रह अगस्त

पंद्रह अगस्त हम सभी को प्यारा
इस पर्व पर होता गर्व बहुत न्यारा

बच्चों पहनकर कपड़े साफ नए
प्रभात फेरी में लिए तिरंगे भी नए

हम देशभक्ति से ओतप्रोत होकर
हाजिर हैं गीत गाना नाटक लेकर

जान अपनी जो गंवा दिए हंसते
उनको याद करो सम्मान के वास्ते

इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी
बच्चों गर्व से भारत माता सदा खड़ी

आजादी का पर्व मनाता झूमता देश
हम सब एक धरे विविधता का वेश।

✍ सूर्यदीप कुशवाहा

लघुकथा

तिरंगे की छांव

सूर्यास्त की लालिमा में डूबा गांव। खेतों से लौटते किसानों के पैरों में थकान, पर आंखों में चमक। आज का दिन कोई साधारण नहीं था। पंद्रह अगस्त की सांझ थी। गांव के चौपाल पर एकत्र होते लोग। बूढ़े रामू काका की आवाज गूंजी, 'आओ भाइयो, आज की रात याद करो उन शहीदों को जिन्होंने हमें यह आजादी दी।' लोगों की भीड़ में एक छोटी-सी लड़की, सीता। उसकी आंखों में उत्सुकता, होंठों पर सवाल। 'दादा, आप बताओ न, आजादी कैसे मिली?' रामू काका मुस्कुराए। उन्होंने सीता को गोद में बिठाया और कहानी शुरू की। कहानी उन वीरों की जिन्होंने अपना सबकुछ देश पर न्योछावर कर दिया। कहानी उन माताओं की जिन्होंने अपने लाल देश को सौंप दिए। सीता की आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, 'दादा, क्या अब हम सच में आजाद हैं?' रामू काका गंभीर हो गए। 'बेटी, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हर बुराई से लड़ने का नाम है। जब तक एक भी बच्चा भूखा सोएगा, एक भी बेटी पढ़ने से वंचित रहेगी, तब तक हमारी आजादी अधूरी है।' तभी दूर से शहनाई की धुन सुनाई दी। आसमान में रंग-बिरंगी फुलझड़ियां। सीता ने अपना छोटा-सा हाथ ऊपर उठाया, जैसे आसमान को छूना चाहती हो। 'दादा, मैं इस आजादी को पूरा करूंगी। मैं पढ़ूंगी और सबको पढ़ाऊंगी।' रामू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सीता को गले लगाया। उस छोटी-सी बच्ची के शब्दों में उन्हें एक नए भारत की आहट सुनाई दी। रात गहरा गई। चांद निकल आया, जैसे इस संकल्प का गवाह बनने। गांव सो गया, पर सपने जाग रहे थे। सपने एक ऐसे भारत के जहां हर नागरिक सच्चे अर्थों में आजाद हो। तिरंगे की छांव में एक नया सवेरा अंगड़ाई ले रहा था।

सीता ने अपने दादा से पूछा, 'दादा, क्या अब हम सच में आजाद हैं?' 'बेटी, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हर बुराई से लड़ने का नाम है। जब तक एक भी बच्चा भूखा सोएगा, एक भी बेटी पढ़ने से वंचित रहेगी, तब तक हमारी आजादी अधूरी है।'

✍ देवेन्द्रराज सुथार

आजादी के मतवालों के प्रेरक एवं रोचक प्रसंग

भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने की लड़ाई में हजारों देशभक्तों का योगदान अविस्मरणीय है। ऐसे ही कुछ प्रमुख देशभक्तों से जुड़े कुछ रोचक तथा प्रेरक प्रसंगों को स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर स्मरण करना प्रासंगिक होगा।

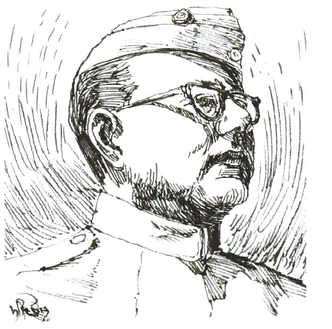

नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवावस्था में जब कॉलेज जाया करते थे, उन दिनों उनके घर के ही सामने एक वृद्ध भिखारिन को भीख मांगते देख सुभाष का हृदय रोजाना यह सोचकर दहल उठता कि कैसे यह बुढ़िया सर्दी हो या बरसात अथवा तूफान या कड़कती धूप, खुले में बैठकर भीख मांगती है और फिर भी उसे दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। घर से उनका कॉलेज करीब तीन किलोमीटर दूर था। प्रतिदिन बस किराये और जेब खर्च के लिए उन्हें जो भी पैसे मिलते, उन पैसों को बचाकर रखते और पैदल ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार प्रतिदिन अपनी बचत के पैसे उन्होंने उस बूढ़ी भिखारिन को जीवनयापन के लिए देने शुरू कर दिए।

गणित और संस्कृत बाल गंगाधर तिलक के प्रिय विषय थे। स्कूल में जब भी परीक्षाएं होती, तब वे गणित के पेपर में हमेशा कठिन सवालों को पहले हल करना पसंद करते थे। उनकी इस आदत के बारे में एक दिन उनके एक मित्र ने पूछा कि तुम हमेशा कठिन सवालों को ही पहले क्यों हल करते हो? अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें परीक्षा में ज्यादा अंक मिलेंगे। इस पर तिलक ने जवाब दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूं, इसलिए कठिन सवालों को पहले हल करता हूं। अगर हम हमेशा वही काम करते रहेंगे, जो हमें सरल लगते हैं तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे।

✍ श्वेता गोयल

सुभाष चंद्र बोस आई. सी. एस. की परीक्षा देने लंदन गए। साक्षात्कार के दौरान एक सदस्य ने एक अंगूठी दिखाते हुए उनसे पूछा, 'मि. सुभाष, क्या आप इस अंगूठी में से निकल सकते हैं?' 'यस सर!' सुभाष चंद्र बोस ने तुरन्त उत्तर दिया। फिर कागज के एक टुकड़े पर उन्होंने अपना नाम लिखा और उसे अंगूठी में से निकाल दिया। फिर यह प्रश्न पूछने वाले सदस्य की ओर मुस्कराकर देखते हुए कहा, 'देखिये, सुभाष अंगूठी में से निकल गया।' आजादी की लड़ाई के दौरान इलाहाबाद में एक दिन महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जुलूस निकाल रहीं थीं और किसी भी पुरुष को चुनौती देकर कह रही थीं कि वे अपने वतन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने एक साथी के साथ उसी समय चंद्रशेखर आजाद वहां से गुजर रहे थे। महिलाओं ने उन्हें नहीं पहचाना और एक महिला ने गरजते हुए उन पर शब्दों से हमला बोल दिया कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। दो-तीन महिलाओं ने आजाद के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि इन्हें चूड़ियां पहनाओ। आजाद मुस्कुराये और अपनी कलाईयां आगे बढ़ाते हुए कहा कि लो बहन! पहना दो चूड़ियां। कुछ देर बाद जब उन्हें आजाद के बारे में सच्चाई पता चली तो वे बहुत शर्मिंदा हुईं।

भारत और सोवियत संघ की संयुक्त सहायता से अंकलेश्वर में तेल के कुएं खोदे गए। उनमें से तेल निकला तो नेहरु जी काफी प्रसन्न हुए और वे कुएं देखने गए तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। अचानक तेल के कुछ छींटे नेहरु जी के कपड़ों पर आ गिरे, जिससे वहां उपस्थित सभी अधिकारी व अन्य व्यक्ति काफी परेशानी में पड़ गए। उन्होंने नेहरु जी से कपड़े बदलने का अनुरोध किया। इस पर नेहरु जी पहले मुस्कराये और फिर गर्व से बोले, 'वाह! इन छींटों को क्यों छिपाऊं? मैं इन्हीं कपड़ों में संसद में जाऊंगा और सभी को शान से दिखाऊंगा हमारे देश में निकले मिट्टी के तेल के धब्बे।'

संस्कृतियां री जातरा : कावड़ यात्रा

(गतांक से आगे)

(चार) डाक कावड़– जियां कि डाका री चिठ्ठी कदी बी केथी बी रुकदी नीं, से एकी हाथो ते दूज्जे हाथो दे लगातार चलदी रओ ई तियां ई ये डाक कावड़ बी लगातार एकि कांधा पांदो ते दूजिया कांधा पांदे तदियो तक चलदी रओई जदियों तक ये आपणे ठीये-ठकाणे नी पहुंची जांदी। खड़ी-कावड़ा रिया ठउणी येसा डाक कावड़ा रे केथी बी, कदि बी, कियां बी रुकणे, झूलणे या जमीना पांदे राखणे रा तो सवाल ई पइदा नी हुंदा। येसा डाक-कावड़ा री ये ही एक खास विशेषता ई कि केवल त्रयोदशिया वाले दिने महूर्तो रे मताबक समें पांदे ही ये शिव जी रे मंदरो दे परवेश कराई होर परवेस करदे सार ई तत्काल कावड़ो दे ल्याये दे तेस पावन गंगाजले की आपणेया टब्बरो रेयो सदस्या, ईष्ट-बंधुआ, गांवो रे भाईया-बंधुआ साथे भगवान शंकरजी रा मंगल गीता, भजना, भेंटा साथे अभिषेक कित्या जाओआ जेसरे पूरे हुणे साथे ई डाक-कावड यात्रा बी सम्पूर्ण मानी जाओई।

(पांच) झिलमिल कावड़– ये कावड़ यात्रा कुछ ही बरसा ते, साला ते अच्छी खासी जादड़ी ई परसिद्धी दिन पर दिन प्राप्त करने लगी री। येसा रा स्वरुप येड़ा ये जेड़ा कि केसी बी महापुराण यात्रा रा हो। बाकाइदा एक 10 ते 10 फुट साईजो रा लकड़िया रे फट्टेया रा एक कमरा बणाया जाओ आ जेते री उच्चाई 15 ते 20 फुटा रे बिच्चे राखी जाओई ताकि से केथी सड़का, बस्तिया दे बिजलियारिया तारी दे नी फसो, केसी किस्मा री कोई जानी मालो री हानी, नुक्सान नी हो। फेर ये कमरा शिव मंदरो रे रुपो दे अति सुंदर ढंगो ते सजाया जाओआ, भान्ति-भान्ति रिया रंग बरंगिया झिलमिल कर दिया सुंदर रोशनिया, लाईटा लगाइया जाओइया जेते कारण ई ये कावड़ झिलमिल कावड़ बोली जाओ ई,मान्नी जाओई। खासकरी की रात के समें झिलमिल करदी रोशनी बहुत प्यारी लगोई से येते किते बी ये झिलमिल कावड़ जाणी जाओई। जेदे गंगा माता रा पवित्र जल मटकेया रे रुपो दे या होरी बड़ड़ेया बर्तणा रे रुपो दे राख्या जाओआ। येस देखदे ई येड़ा लगोआ मानो साक्षात शंकर भगवान जी येते मंदरो दे बराजमान ये। येस झिलमिल कावड़ यात्रा री खास बात ये है कि येते पीछे समूहो रे रुपो दे, जत्थे रे रुपो दे काफी भगत जनाना मर्द भजन वाणी गांदे बजांदे चली रहोए।

जात्रा ते पहिले केसी बी बस्ती, गांव या मुहल्ले रे भगत लोक ये तय करोये कि कम ते कम 25-30 मजबूत, पक्के लोक जो कि येसा झिलमिल कावड़ा चक्की सकोए साथे गंगा तटो पांदे हरिद्वार जाणे चाहियो जेथा ते ये जात्रा शुरु हो ई। फेर येते ते लावा जात्रा री शोभा बढाने खातर सम्बंधित गांव, मुहल्ले, कस्बे, शैहरो ते जितने बी लोक आपणिया ईच्छा ते कीर्तण करदे या भजनवाणी करदे चली सकोए, खुश हुई की जाई सकोए। कउंकि 25-30 लोका खे चाह पाणी खाणा पीणा करने वाले बी तो साथे चाहियो। हालांकि जगहा-जगहा कावड़ शिवर लगे दे हो ये। भगत लोक कावड़िया री बहुत सेवा करोए पर कई जगहा शैहरा, कस्बेया ते बाहरे येड़िया बी होइया जेती की रोटी पाणियो री कोई व्यवस्था नी हुई सकदी।

(छह) पीठ्ठू कावड़–ये कावड़ बहुत ही सरलता ते, आरामो ते पीठ्ठू झोले रे रुपो दे पीठी पांदे चक्की जाओई ताकी चलणे दे आराम मिलो, असानी हुई सको। येदे कावड़िये गंगाजलो री छोटी गेलण, बोतल आदि पीठ्ठू झोले दे गंगातटो ते भरी की चलोए। बाकी सारे सब नियम पहिले जे रओए।

(सात) बाल कावड़– निक्के निक्के बालक आपणे मताबाक छोटे-छोटे कावड़ बणाईकि इन्हा कावड़ा आपणीया कांधा पांदे, पीठी पांदे लई की चलोए। इन्हा बाल कावड़िया रा रुप देखी की तो येड़ा लगोआ मानो साक्षात भगवान शंकर या माता पार्वतु ई बाल रुपो दे आइगे दे। दुनिया इन्हा देखी की बहुत ई परभावित होई।

(आ) घरो ते गंगा जी ते कावड़ ल्याउणे खातर प्रस्थान करने ते बाद हरिद्वार पहुंचणे तक होर तेते ते बाद कावड़ यात्रा पूरी हुणे तक कावड़िया द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ विशेष सख्त नियम :-

पहला नियम तो ये आ कि हरिद्वार पहुंची की सबनी ते पहिले 'कनखल् गंगा स्नान' करने ते बाद कावड़ ल्याउणे रा काम शुरु करना चाहियो।

दूज्जा नियम ये आ कि कावड़ यात्रा रे दौरान केसी बी परकारा री दांतुन या ब्रुश-पेस्ट नी करना चाहियो। केवल साफ़ पाणियो रा ही कुरला करना चाहियो।

तीज्जे नियमो रे मुताबिक कावड़िये ये खास ख्याल राखणा चाहियो कि जिन्हा टाल्या,वस्त्रा पहिनी की से नहाणे धोणे, रोटी पाणी, चाय पीणे, टट्टी पसाबे जाई रा या सई रा तेस तेते बाद आपणा टाल्ला थिप्पा बिना केसी साबणो ते साफ पाणियो दे पखाली की, सुखाई की दुबारा पहिनणे चाहियो। साबणो रा इस्तेमाल पूरा

बर्जित आ।

चौथा नियम बोलोआ कि कावड़ जात्रा रे दौरान वस्त्र धोणे खातर केसी बी किस्मा रा साबण, पाउडर इस्तेमाल करना सख्त मना ये।

पांचवे नियमो मताबक हरकिया पइडिया पांदे मांता गंगा री प्राथना ते बाद 'जियां ई गंगाजल कावड़ो दे भरेया बस तेस ई बख्ते, तत्काल आपणे मनो दे ये संकल्प लई लो कि येसा जात्रा रा सरुप क्या हुणा जियां कि-डाक कावड़, खड़ी कावड़, झूला कावड़ या बैठी कावड, पीठ्ठू कावड़ आदि-आदि। येते ते बाद जेडिया कावड़ा रा संकल्प कित्या तेडे ई नियमो रा पालन करना जरुरी हुई जाओ आ।

✍ यादव किशोर गौतम

छठ्ठा नियम बोलोआ भई कावड़ बदलदे समें समय येसा गला रा बसेस ध्यान राख्या जाओ कि भूली की बी कावड़ आगले कनारो ते, मुंहो रे सामणे ते नी बदलेया जाओ। कउंकि येडा करने ते कावड़ियो रे मुहों रे निकले जूठे साहे कि से पवित्र कावड़ जूठा, दूषित हुई जाओआ। येस खातर हमेसा ही कावड़ पिछ्ले कनारे पीठी रिया साइडा ते घुमाई की ई एकि फरकुओ पांदो ते दूजे फरकुओ पांदो खे बदलेया जाओ।

सप्तम् नियम आदेस देओ आ कि भ्याहगा सांझा कावड़िया आपणे जिउओ रे पूरे भावो साथे आपणे पवित्र कावड़ो रेया दूही गंगाजलो वालेया पल्लेया खे गंगामाता, भगवान शंकर मानी की यथा शक्ति धूप देओ,भोग लगाओ, आरती गाओ।

आठवें आखरी नियमो मताबक ये ध्यान राख्या जाणा चाहियो कि केसी बी सूरती दे कावड़ो थाल्लिये कुत्ता, बिल्ला या कोई होर जीव जंतु नी निकल्ना, जाणा चाहियो। कउंकि येडे अपवित्र जीवा रे निकलने ते सारी की सारी कावड़ यात्रा निष्फल हुई जाओई।

(इ) बिच्च रास्ते, बाटा दे कावड़ो खे किया विश्राम कराणा चाहियो, येते खातर म्हारे संते, ऋषि-मुनिये जो नियम बणाई राखे, बहुत जरुरी आ तिन्हा रा पालन करना-

पहला-इना सबनी कावड़ा बिचो ते सिर्फ होर सिर्फ झिलमिल कावड़ा ही धरतिया पांदे राखी सकोये। या फेर तख्तपोष, प्लास्टिको री कुर्सी इस्तेमाल करी सकोए।

दूजा-भूली की बी, कदि बी कावड़ गूलरो या उमरी रे डाळो दे नी टांगणा चाहियो या येते नेहठे नी राखणा चाहियो। येते ते जात्रा निष्फल हुई जाओई यात्रा रे दौरान हर परकारा ते पूर्ण सावधान रैहणे रे उद्देश्य ते जगहा-जगहा स्वागतकर्ता भगतगण आपणेया कावड़ शिवरा दे येस **'कावड़ गीतो'** री मार्फत कावड़िया खे सावधान रैहणे खातर सदा याद करांदे रओए कि-

सावधान ओ भाई ! सावधान!
पेड़ गूल्लर का जोई, ना टांगे
कावड़ कोई
यात्रा होगी निष्फल, बचना रे ओ
भाई ! - 2
दाएंबाएं देखो रे बाटा, गूलर पे
लगा है काटा
बचना! बचना भाई! रे बचना!
बचना! भाई-बमबम बोल।।5।।
(श्रीरुप-पद्म भजनमाला)

तीजा नियम अगाह करोआ कि - नवारी वाली सूती पौंहे प्लास्टिक वाली बुणी दी चारपाई, फोल्डिंग चारपाई या ऐसी कुर्सी जेते दे जालिया वाली बुणती हो, नवार लगी दी हो, इन्हा रा इस्तेमाल करना पूरी तरहा बर्जित आ। कारण ये 'नवार बूणी' कुर्सी तो माया रा बुणयादा जाल आ। से येस खातर येते ते बचणा चाहियो। येड़िया चीजा ते कनारा ही करना चाहियो।

(ई) कुछ विशेष मर्यादा जो कावड़ यात्रा पूरी हूणे तक 'कावड़िया रे टब्बरो वालेया' खे बी मान्नणिया जरुरी ये- कावड़ यात्रा रे चौथे अंगो दे आपू बी कई बार कावड़ ल्याई चुके 'जंगम बाबा श्री सुनील जी' रे मताबक कावड़ यात्रा रे समे, यात्रा री निर्विघ्नता पूर्वक समाप्तिया खातर संत-महात्मेया घरे रहणे वाले 'कावड़िया रे परिवारो रेया बाकीसदस्या जियां कि माता, भाई, पत्नी या बाल्का खे बी कुछ विशेष नियम, मर्यादा नधारत करी राखिया, जिन्हा बिच्चे-

पहिली मर्यादा रे अनुसार जदियो तक 'कावड़ यात्री घरे वापस नी आया तदियो तक सींका, छाट्टेया, टण्डोरे वाले झाड़ूये कि आंगण द्वार साफ नी करना। केवल फूलवाला या खजूरी रा नरम झाड़ू ही आंगणो दे सूहण-प्वाहर करने खे इस्तेमाल करना।

दूज्जी मर्यादा रे मध्यनजर जेबे घरे कुछ बी भोजन-पाणी बणाणा तो सलादो रे रुपो प्याज, लहसण या होर कोई तामसिक चीजा रा बिल्कुल प्रयोग नी करना होर न ही दाली सब्जिया दे इन्हारा इस्तेमाल करना। खास बात ये कि दाली, सब्जिया खे केसी किस्मा रा कोई तुड़का मतलब छौंक जो की चसड़िई री वाज करो, नी लगाणा। कउंकि येड़ा करने ते कावड़ ल्याउणे वालेया रे पईरा दे छालू बगैरा पड़ी सकोए जेते कित्ते तिन्हारा हाण्डणा मुश्कल हुई जाणा। तिन्हा री यात्रा बहुत इ तकलीफ देह हुई जाणी। हां सलूणे दे इन्हादे पकदे-पकदे घीउ जरुर पाई सकोए।

तीज्जिया मर्यादा मुताबिक एस दौरान पीछे सारा टब्बर पूर्ण रुपो दे सात्विक रहणा चाहियो। केसी किस्मा रा संगार, सजावट, या संगारो रा समान जियां कि ईत्र-फुलेल इस्तेमाल नी करना चाहियो। कउंकि ये रजोगुण बढ़ाणे वाली चीजा ई आ। येते खातर पूर्ण रुपो ते सात्विक रहणा चाहियो।

चौथी मर्यादा कावड़िये रे परिवार वालेया खे यात्रा रे दौरान केसी बी सूतको, पातको वालेया रे घरे जाणे री साफ मनाही करोई। येते कारण बी यात्रा दे केसी बी किस्मा री अड़चण आई सकोई।

संत-स्थापित पांचवीं मर्यादा मताबक कावड़िये यात्रा पूर्ण करदे हुए जियां ईआपणे आपणे गांव, बस्ती, मुहल्ले दे पहुंचोए, गांव वालेया चाहियो कि सबनी ते पहिले स्यो केवल र केवल तेतो रे स्थानिय शिव मंदरो दे ई नीये जाओ।

खुदा न खासता अगर पहुंचणे वाले दिने शिवत्रयोदशी नी हो मतलब द्वादशी तिथी हो तो रात भर भजन वाणी, कीर्तन करो। तो आपणे गांव रे सभी बंधु-बांधवा, ईष्ट मित्रा साथे परोहत, पण्डतो बुलाई की "भगवान शंकर जी रे अभिषेको रा महूर्त कढाई की आपणे गांवरेया सबनी भाईया बंधुआ साथे शिवजी रा अभिषेक करो। होर जे पहुंचणे वाले दिने ही **'श्रावण शुक्ल त्रयोदशी'** हो तो तेस ही समें बिचे तत्काल ही भोले बाबे रा अभिषेक करी देयो।

छठी मर्यादा के मुताबिक कार्य पूर्ण हूणे पांदे 'कन्या-पूजन' तो अवश्य करना चाहियो ।

सातवीं मर्यादा ये बोलोई है कि अगर लोका दे समर्था, पर्पण, गुंजाईस हो, होर अंदरुनी इच्छा बी हो तो कल्ले या सामूहिक रुपो दे मिली-जुली की से भोले शंकर जी रे नांवे भण्डारे रा आयोजन भी करी सकोए होर एस प्रकार निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता हुई समाप्ती जाओई परम पावन कावड़ यात्रा री।

येबे अखीर प्रस्न ये उठोआ कि लगातार एकी महीने तक चलणे वाले एस कावड़ महापर्वो ते आध्यात्मिक लाभो रे लावा जनता, परदेसो, देसो खे क्या मिलोआ? कउं सरकारा येसा यात्रारिया बगैर केसी अड़चणा ते समाप्त हुणे रिया तई कउं इतना तगड़ा इंतजाम करोइया?

कउं पूरा जोर येड़िया यात्रा, उत्सवा रे आयोजना पांदे लाओईया? तगड़ा खर्व करोइया? ये बात सदा याद राखणे री ये कि यो जितने बी राष्ट्रीय उत्सव ये, यात्रा ई आ, महापर्व ये, यो आपणे-आपणे ढंगो ते देसो री जनता होर सरकारा दोनी री ही कड़ी परीक्षा लंदे हुए दूहीं खे ऐन कसौटिया पांदे परखोए। कड़ी परीक्षा लओए।

पहिले तरीके तो ये महानयात्रा, मेले या कुम्भ जे बसाल आयोजन देशोरिया की जनता खे परखदे हुए, कसौटिया पांदे कसी की येड़ा पता लगाओए कि क्या म्हारे देसो री जन्ता रा आपणिया संस्कृतिया, आपणेया रीती-रवाजा, आपणिया पुश्तैनी बरासती रे परती, सही माइनेया दे पूरा प्रेम, श्रद्धा होर आदर आ कि ना?

क्या जनता इन्हा सबनी रा रखरखाव, संरक्षण करदे हुए आगलिया पीढ़िया तक पहुंचाणे रिया तई आपणी पूरी जिम्मेदारी समझोई या कि ना? कारण ये आ कि 'जन्ता जितणी जादा जागरुक हो ई, सरकार बी तितणी ही चतन्न, चुस्त रहो ई, चोखा काम करोई। सदा सावधान रहो ई। **दूजे तरीके यो महाआयोजन तिन्हा मौजूदा सरकारा खे ऐन कसौटिया पांदे लाई की राखोए जेथो ते इन्हा यात्रा रा, आयोजना री शुरुआत हो ई**, होर फेर जिसिये जिसिये जिन्हा जिन्हा प्रान्ता रिये इन्हा रा आपणेया आपणेया ठकाणेया तक गुजरना, जाणा हो आ। (क्रमशः)

जात्रा ते पहिले केसी बी बस्ती, गांव या मुहल्ले रे भगत लोक ये तय करोये कि कम ते कम 25-30 मजबूत, पक्के लोक जो कि येसा झिलमिल कावड़ा चक्की सकोए साथे गंगा तटो पांदे हरिद्वार जाणे चाहियो जेथा ते ये जात्रा शुरु हो ई। फेरे येते ते लावा जात्रा री शोभा बढाने खातर सम्बंधित गांव, मुहल्ले, कस्बे, शैहरो ते जितने बी लोक आपणिया ईच्छा ते कीर्तण करदे या भजनवाणी करदे चली सकोए, खुश हुई की जाई सकोए।

कबता

बरसाती साही गल नीं

बदल ता भतेरे छाई कराएं।
पर पाणी री बूंद सटणें ते परहेज करी कराएं।।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।
सुगला ता मुटणे थी लगीरी।
पर खाडा नालिया सुक्की पईरी।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।।
मयान ता हुई गईरे।
पर डोहरू ता पाणी बगैर सुक्के पईरे।।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।
हाड़ा ता चलो बरखा कम हुई।
पर सौण महीने ता खाडा नालिया अवार पार हुई।।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।
छलिया आजा जो लक्का लक्का तक थी पुजाहीं।
हुण ता छलिया डोहरूआ टोलणे पैई कराहीं।।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।
खाडा ले लंघणा नी हुंदा था खाला जी का बाड़ा।
आज काले ता मकोड़िया भी लंघी कराहीं वारा पारा।।
हाई ता बरसात ही पर बरसाती साही गल नीं।

✍ विनोद वर्मा

आपदा प्रभावित परिवारों को आगामी....

(पृष्ठ एक का शेष) राशि का 80 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर किया गया है।

हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर-खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा, नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में दो रुपये प्रति टन शुल्क लिया जाएगा।

गैर-खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75 प्रतिशत (140 रुपये प्रति टन) प्रसंस्करण शुल्क सरकार को देय होगा। मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमण्डल ने रसायनमुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हिम उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कृषि समुदायों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो और मक्का को 30 रुपये प्रति किलो खरीदने की योजना है।

मंत्रिमण्डल ने पशु पालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान इस उप-समिति के सदस्य होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। बैठक में राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति-2014 के तहत 60:40 की शर्तों में ढील देने को सहमति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) नियम-2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है। शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खण्डों में जल शक्ति विभाग के नए उप-मण्डल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप-तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी। बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के गलोड़ में नव सृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

महान लोकतंत्र का गौरवपूर्ण उत्सव

(पृष्ठ एक का शेष) फौज का हिस्सा बनकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया तथा विदेशी दासता से देश को मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों तक की आहूति दी। महात्मा गांधी सहित देश के अनेक बड़े नेता समय-समय पर प्रदेश आते रहे ताकि स्वाधीनता प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा सके।

स्वाधीनता प्राप्ति के ठीक आठ माह उपरान्त 15 अप्रैल, 1948 को लगभग 30 पहाड़ी रियासतों के विलय के उपरान्त हिमाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आया। उस समय यह पहाड़ी प्रदेश गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक बदहाली व पिछड़ेपन की तस्वीर था। लोग भी मान बैठे थे कि गरीबी ही पहाड़ों की नियती है। परन्तु यहां के मेहनतकश व ईमानदार लोगों तथा अधिकतम समय प्रदेश को मिले कांग्रेस के ईमानदार, सशक्त व दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हिमाचल प्रदेश वर्ष दर वर्ष विकास के नए-नए सोपान छूता रहा और आज इसकी गिनती देश के कुछ चुनिंदा विकसित राज्यों में की जाती है।

वर्ष 1948 में जहां प्रदेश की साक्षरता दर केवल 4.8 प्रतिशत थी वह आज बढ़कर लगभग 84 प्रतिशत पहुंच गई है। प्रदेश में उस समय केवल 331 शिक्षण संस्थान थे जिनकी संख्या आज लगभग 16,200 के अधिक हो गई है। इसी प्रकार उस समय केवल छः गांव ही विद्युतिकृत थे जबकि आज हिमाचल प्रदेश में शत-प्रतिशत विद्युतिकृत राज्य होने का गौरव प्राप्त है।

वर्ष 1948 में प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय केवल 240 रुपये थी जबकि आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये हो गई है। व्यवस्था परिवर्तन तथा लीक से हटकर कार्य करने के संकल्प के साथ दिसम्बर, 2022 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सत्ता में आई वर्तमान प्रदेश सरकार ने लगभग 19 महीनों के कार्यकाल में प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, उससे साफ होता है कि यह सरकार केवल कहने में नही करने में विश्वास रखती है। गत वर्ष प्रदेश भर में भारी वर्षा, भूस्खलन बाढ़ के कारण प्रदेश को जानमाल व संपत्ति को भारी क्षति हुई तथा राज्य की आर्थिकी पर इसका बुरा असर पड़ा। मगर जिस सूझबूझ व राजनीतिक परिपक्वता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस स्थिति से प्रदेश को उभारा, वह निःसंदेह एक सराहनीय व अनुकरणीय है।

कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने वर्षों से चले आ रहे राहत एवं पुनर्वास नियमों में बदलाव किया तथा प्रदेश के लिए राज्य संसाधन से ही 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे सत्ता सुख के लिए नहीं अपितु प्रदेशवासियों के सुख-दुःख बंटने व प्रदेश के विकास के लिए सत्ता में आए हैं।

बात चाहे वर्षों से पुरानी पेंशन की बहाली का इंतजार कर रहे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की हो या मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की है या अनाथ बच्चों के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' घोषित करने की, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की या मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के तहत ऐसी सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा का व्यय सरकार द्वारा वहन करने की, ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों व जरूरतमंदों के कल्याण व उत्थान के प्रति वचनबद्ध है।

प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। जहां एक ओर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू कर युवाओं को स्वरोजगार की योजनाएं अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है, वहीं दूसरे चरण में छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।

राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी निःसंदेह सराहनीय है। इससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को उनके घरों के समीप ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

हिमाचल प्रदेश के स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश के हरित ऊर्जा राज्य बनाने की एक सराहनीय पहल की गई है। इसके लिए प्रदेश में ई-वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में हरित उद्योगों को विशेष तरजीह दी जा रही है तथा सौर ऊर्जा के दोहन को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में किसानों व बागबानों की आर्थिकी में सुधार लाया जा सके इसके लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। बागबानों की सुविधा के लिए इस वर्ष से सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू किए गए हैं।

सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में भी रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। दूध आधारित ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की हिम गंगा योजना शुरू की गई है तथा कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सभी वर्गों के कल्याण तथा सभी क्षेत्रों का समान विकास ही वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों से आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध व खुशहाल राज्य बन कर उभरेगा।

कैंसर उपचार सुविधाओं....

(पृष्ठ एक का शेष) है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार कैंसर डे-केयर सेंटर चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर रही है। प्रथम चरण में 13 अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके दूसरे चरण में 27 हाई लोड सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह सेंटर स्थापित होंगे और तीसरे चरण में 28 संस्थानों में डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कैंसर डे-केयर केन्द्रों में पेल्लीएटिव केयर यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहां न्यूक्लियर मेडिसन का विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी क्षमता की न्यूक्लियर लैब और साइक्लोट्रोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल सुपर स्पेशिएलिटी संस्थान चमियाणा में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी आरंभ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री आरंभ की जाएगी। इसके तहत कैंसर के मामलों व संख्या का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में कैंसर के मामलों की स्क्रीनिंग के लिए एक जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बैठक में बहुमूल्य सुझाव दिए।

चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध...

(पृष्ठ एक का शेष) के लिए पंजीकरण काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को चिकित्सक से परामर्श के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने टांडा महाविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में 100 बिस्तर क्षमता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ विकसित किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही कार्यशील कर दिया जाएगा तथा बीएससी नर्सिंग कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने महाविद्यालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरा मेडिकल तथा अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति भी दी। उन्होंने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की समीक्षा करते हुए इसमें विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित सभी निर्णय व्यापक स्तर पर जन कल्याण भावना के दृष्टिकोण से लिए जाएं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में विभिन्न भवनों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग में 1,43,291 मरीजों, आर्थोपेडिक्स विभाग में 85,161, जनरल सर्जरी विभाग में 77,012 मरीजों सहित सभी विभागों में 8,72,829 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया।

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने....

(पृष्ठ एक का शेष) को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध पूर्ण करने के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इन परियोजनाओं से प्रदेश के लोग आजीविका कमा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं बोनाफाइड हिमाचलियों को आवंटित की जाएगी और प्रदेश के लोगों को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसलिए जल विद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रख-रखाव आसानी से किया जा सकता है और इनका जीवनकाल भी लम्बा होता है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार हरित पहल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य रही है। प्रदेश सरकार ई-वाहनों के संचालनों को बढ़ावा प्रदान कर रही है और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों के बेड़े में परिवर्तित किया जा रहा है।

लांस नायक प्रवीन शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लांस नायक प्रवीन शर्मा (26) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने भी शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

लांस नायक प्रवीन शर्मा 10 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन रक्षक के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। वह वन पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे।

मुख्यमंत्री ने किया 'नशे से तुम दूर रहो' गीत जारी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला की सामाजिक कार्यकर्ता तरुणा मिश्रा द्वारा निर्मित 'नशे से तुम दूर रहो' गीत जारी किया। इस गीत के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक नवीन पहल की हैं। उन्होंने युवाओं से रचनात्मक और स्वस्थ समाज बनाने के लिए नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन समाज को जागरूक करने में राज्य सरकार के प्रयासों को सम्बल प्रदान कर सकते हैं। समाज के हर वर्ग को इस खतरे से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। तरुणा मिश्रा ने कहा कि वह नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने प्रयासों को निरन्तर जारी रखेंगी।

ब. अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जुन्गा जिला शिमला हि.प्र.

मुकदमा :- दरुस्ती इन्द्राज जेर धार 37 हि.प्र.

मुकदमा नम्बरान :- 3/2024

शिर्षा :- विरेन्द्र कुमार, कमल किशोर व रजनीश कुमार बनाम सुरनामल

इश्तहार बनाम :- श्री सुरनामल पुत्र करनाल्ली पुत्र नामालूम निवासी गांव व डाकघर कोटी तहसील जुन्गा जिला शिमला हि.प्र.।

ईश्तहार/नोटिस

इस ईश्तहार के माध्यम से आप को सूचित किया जाता है कि श्री विरेन्द्र कुमार, कमल किशोर व रजनीश कुमार पुत्रगण आज्ञा राम निवासीगण कोटी डाकघर कोटी तहसील जुन्गा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने खाता/ खतौनी न. 215/245 खसरा नम्बर 707 रकबा 0-00-38 हैक्टेयर में खाना काश्त का इन्द्राज दरुस्त करने हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त केस दिनांक 31/08/2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुनिश्चित हुआ है। अतः इस ईश्तहार के माध्यम से मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि उनवान वाला में मुकर्रर तारिख पेशी को प्रातः 11:00 बजे स्वयं या वकालतन हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 30/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा कार्यालय से जारी किया गया।

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि.प्र.)

डाक पंजीकरण संख्या : एच.पी./42/एस.एम.एल. 2024-2026 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन से सुनिश्चित होगी निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रणाली में संशोधन की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों के मूल्यांकन को सीधे उनके कार्य परिणामों से जोड़कर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों और जिलों में तैनात उपायुक्तों सहित सभी अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके एपीएआर के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत जैसी पारंपरिक वर्णनात्मक श्रेणियों को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया जाएगा। उनकी वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धियां, अन्य कार्य-संबंधी विशेषताएं और व्यक्तिगत व कार्यात्मक विशेषताएं सुधारों में नकारात्मक अंकन भी शामिल है। अधिकारियों का मूल्यांकन तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी आदेशों या परामर्श का पालन न करने पर अधिकारियों के 1-10 के मापदण्ड पर अपने समग्र ग्रेड से दो अंक कम होने की भी संभावना हो सकती है।

वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन का निर्णय

मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता को एक प्रमुख मापदंड के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनका मूल्यांकन प्राप्त होगा, जो कार्य को बढ़ावा देगा और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहित करेगा। एपीएआर प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे संचालन सुव्यवस्थित होगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह संशोधन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, विशेष रूप से क्षेत्र-स्तर के अधिकारियों के लिए, जिनका प्रदर्शन मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि उच्च प्रबंधन अधिकारियों का गुणात्मक पहलुओं और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं और इससे प्रशासन के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू डॉ. यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए

हिमकेयर को बनाया जाएगा अधिक सुदृढ़ : उप-मुख्यमंत्री

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमकेयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री अग्निहोत्री गत दिनों शिमला में हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया है, जो सरासर गलत है। राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा जारी रहेगी। हिमकेयर कार्ड से स्वास्थ्य लाभ लेने पर सरकार

मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक

द्वारा हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कुल 457 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लेने वाले पांच लाख 32 हजार परिवार ही पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे 14 लाख 83 हजार परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

इस वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में ही यह 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। शेष बचे महीनों में आयुष्मान के तहत सभी देनदारियों का भुगतान प्रदेश सरकार को करना होगा।

मुख्यमंत्री से लूहरी और सुन्नी परियोजना प्रभावितों की भेंट

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से गत दिनों शिमला में पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लूहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजना प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी सरकार द्वारा मांगी गई रॉयल्टी प्रतिशतता पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए 210 मेगावाट लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना तथा 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगी।

प्रदेश सरकार करेगी 327 करोड़ से ई-बसों की खरीद

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी।

ई-बसों की खरीद से हरित ऊर्जा राज्य का सपना होगा साकार : मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है और निगम के 12 हजार कर्मचारी इस संस्था की नींव हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और अतिरिक्त दो हजार टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम धार्मिक स्थानों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में पहले चरण में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के लिए छह बसों की सुविधा दी गई है। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में निगम विश्वसनीय परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि गत सात माह से निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को हर माह के पहली तारीख को वेतन और पेंशन मिल रहा है, जबकि पिछली सरकार के दौरान कर्मचारियों और पैंशनरों को आठ से दस दिनों के बाद वित्तीय अदायगी की जाती थी। अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निगम के प्रबन्ध निदेशक रोहन चंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

प्राकृतिक खेती को संबल प्रदान करेगी 150 करोड़ की हिम-उन्नति योजना

प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए हिम-उन्नति योजना लागू करेगी जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 1.92 लाख किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवाहरिक बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा।

हिम-उन्नति योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को एकीकृत करेगी ताकि वह बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकें, जिससे पर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष सुनिश्चित हो सके। यह पहल प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं को भी एकीकृत करेगी। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास जैसे विभाग समन्वय से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार और समाज के कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना से 2600 केंद्रित कृषि समूहों के निर्माण से लगभग 50 हजार किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा राज्य में सब्जियों और अनाजों की उत्पादकता में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। हिम-उन्नति योजना के तहत मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के

योजना से मिलेगा 1.92 लाख किसानों को प्रोत्साहन

लिए 100 प्रतिशत मृदा परीक्षण-आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, उच्च-स्तरीय उत्पाद की खेती को बढ़ावा और पारंपरिक फसलों और बाजरा खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये और कांटेदार तार इत्यादि लगाने के दृष्टिगत अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद की जाएगी। इसके तहत 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मक्का की खरीद की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। हिम-उन्नति योजना राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण के तहत प्राकृतिक खेती के तरीकों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से 15 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती की भूमि के रूप में प्रमाणित करने की योजना है। कृषि संसाधन विश्लेषण (सीईटीएआरए एनएफ) प्रणाली के लिए प्रमाणित मूल्यांकन उपकरण के तहत 1.41 लाख से अधिक किसानों को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में विशेषकर महिला किसानों के बीच प्राकृतिक खेती की लोकप्रियता बढ़ रही है। हिम-उन्नति योजना कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

चंबा में 120.44 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर 120.44 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। उन्होंने मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण वह व्यक्तिगत रूप से मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाए।

मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से मिंजर मेले का समापन किया

उन्होंने मिंजर मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने चंबा के लिए 120.44 करोड़ की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखीं। उन्होंने चंबा में 35.38 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन और पुलिस मैदान चंबा में 11.12 करोड़ से निर्मित होने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चंबा में पांच करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने 4.64 करोड़ रुपये की लागत से बहुद्देशीय हॉल और डाइट सरू पुस्तकालय की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 10.38 करोड़ से नव-निर्मित ट्रॉमा केयर सेंटर और 20.58 करोड़ से निर्मित विद्युत उप-केंद्र का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा में 11.57 करोड़ से निर्मित पीजी ब्लॉक, तीसा में 1.68 करोड़ से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागीगढ़ और तीसा के भंजराडु में 6.11 करोड़ से नवनिर्मित बस अड्डे का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा हेलीपोर्ट का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा और यहां उड़ानों के लिए उपदान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा-चुवाड़ी-जोत सुरंग निर्माण की कंसल्टेंसी के लिए चार करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की सभी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास की गाथाएं लिखी हैं।

प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादकः राजीव कुमार, एच.ए.एस., निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. शिमला-171002, मुद्रकः प्रभा राजीव, नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-171005, फोनः 2830381-PBX.A29,, वरिष्ठ सम्पादक : डॉ. राजेश शर्मा, सम्पादकः रीना नेगी
कार्यालयः हि.प्र. मुद्रणालय परिसर, शिमला-171005, फोनः 2633145 व फैक्सः 2830374, ई-मेलः girirajhp@gmail.com. प्राप्ति स्थानः गिरिराज कार्यालय। (गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं)